।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

• वर्ष-6
• अंक-46
रायपुर, शुक्रवार 25 सितंबर 2026
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> युवा शक्ति विकसित भारत और ...

राहुल गांधी का राजनीतिक ज्ञान शून्य : सुधांशु

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनावी व्यवस्था और एंटी-इन्कंबेंसी को लेकर दिए गए बयानों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा पेश की गई जानकारी का स्रोत और आधार स्पष्ट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास और अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के सत्ता में रहने के रिकॉर्ड को ठीक से नहीं समझते।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपीटी के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन इसमें जिन स्रोतों और रिपोर्टों का इस्तेमाल किया गया, उनका आधार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऐसे स्रोत हैं, जिनकी विश्वसनीयता और पहचान को लेकर सवाल हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को भारतीय राजनीति की वास्तविकता को समझने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के अलग-अलग राज्यों में सत्ता में रहने के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के एंटी-इन्कंबेंसी वाले तर्क पर सवाल उठाया।

तमिलनाडु से बंगाल तक कांग्रेस के सत्ता रिकॉर्ड का जिक्र

त्रिवेदी ने कहा कि तमिलनाडु में 1967 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था। पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बनी। 1977 में राज्य में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया और लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा का भी उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में भी लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। त्रिवेदी ने इन्हीं उदाहरणों के आधार पर राहुल गांधी के एंटी-इन्कंबेंसी संबंधी बयान पर सवाल उठाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक समय चुनाव प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताओं की खबरें सामने आती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों की लूट और हिंसा जैसी घटनाएं होती थीं। उन्होंने कहा कि आज चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल होता है और स्वतंत्र मीडिया भी मौजूद है। भाजपा नेता ने दावा किया कि ऐसी व्यवस्था आने के बाद कांग्रेस के लिए सत्ता में वापस आना मुश्किल हुआ है।

हमें 100% यकीन कि चुनावों में धांधली हुई : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में चुनावी व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गड़बड़ियां हुई हैं और उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा मामला है।

राहुल गांधी ने कहा कि वह यह बात बिना आधार के नहीं कह रहे हैं। उनके मुताबिक, उनके पास मौजूद जानकारी और सबूत इस बात को 100 प्रतिशत निश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय चुनावों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के वोट की सुरक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर वोट की व्यवस्था कमजोर होती है तो संविधान अपनी ताकत खो देता है और उसके बाद कानून तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ता है।

कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ संगठन मंत्री की जिम्मेदारी

पवन साय बने झारखंड के नए संगठन महामंत्री

रायपुर/रांची। भारतीय जनता पार्टीके केंद्रीय नेतृत्व ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर के कई राज्यों में बड़े स्तर पर नेताओं के जिम्मेदारी में फेरबदल किया है. इस सांगठनिक फेरबदल में झारखंड भी शामिल है. प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री के पद पर अब पवन साई की नियुक्ति की गई है. वहीं, अब तक झारखंड के संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल रहे कर्मवीर सिंह का तबादला कर उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया है.

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) के रूप में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी है. उनका मुख्य केंद्र भुवनेश्वर होगा. सौदान सिंह इन राज्यों में बीजेपी के सांगठनिक कामकाज और आपसी समन्वय की निगरानी करेंगे.

पवन साय लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं. संघ से भाजपा में आने के बाद वे संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटे रहे. करीब 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रदेश संगठन महामंत्री के महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहे. छत्तीसगढ़ में ओम माथुर के साथ मिलकर साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की वापसी कराने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. उनके कार्यकाल में ही भाजपा ने राज्य में 15 से 54 सीटों पर छलांग लगाई थी. उन्हें शांत, अनुशासित, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखने और विवादों से दूर रहने वाले रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है.

संगठन महामंत्रियों के बीच काम का बंटवारा

केंद्र और राज्यों के संगठन महामंत्रियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। शिवप्रकाश को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गई है। वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में कार्य करेंगे। शिवप्रकाश का केंद्र मुंबई में रहेगा। वहीं, सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) का दायित्व मिला है। वह बिहार, झारखंड, ओडिश और पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका केंद्र भुवनेश्वर में रहेगा। साथ ही, वी. सतीश को एससी, एसटी मोर्चा, संसदीय कार्यालय संगठक का दायित्व दिया गया है। वहीं, नागेंद्र को संगठन के रूप में वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, अजय जामवाल को प्रदेश महामंत्री (संगठन) महाराष्ट्र का दायित्व मिला है।

मधुकर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बनाया गया है। साथ ही, दशरथ को प्रदेश सह महामंत्री (संगठन) तेलंगाना नियुक्त किया गया है। वहीं, रवींद्र राजू को प्रदेश महामंत्री (संगठन) असम, त्रिपुरा, कार्यालय निर्माण का दायित्व मिला है।

बता दें कि पवन साई को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बिहार और सिद्धार्थन को प्रदेश महामंत्री (संगठन) हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मिली गई है। साथ ही, रत्नाकर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) गुजरात, दादरा नगर हवेली × दमन एवं दीव व अरुण बिन्नाडी को प्रदेश सह महामंत्री (संगठन) का दायित्व मिला है।

पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

एफआईआर होते ही गिरफ्तारी पर रोक, कस्टडी पर भी असर नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद और बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामलों में पॉक्सो कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय तय किए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये उपाय उन मामलों में लागू होंगे, जहां बच्चे के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा हो और बच्चे के साथ रहने वाले किसी माता-पिता या परिवार के सदस्य पर पॉक्सो के तहत यौन अपराध का आरोप लगा हो। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि इन उपायों का मतलब पॉक्सो कानून को कमजोर करना नहीं है। यह कानून बच्चों को यौन हमला, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। शीर्ष कोर्ट

ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे की सुरक्षा और आरोपी को होने वाले गंभीर नुकसान, दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी को जल्दबाजी में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 में गिरफ्तारी को लेकर जो नियम हैं, उनका सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस को शिकायत मिलते समय यह भी देखना होगा कि बच्चे के माता-पिता के बीच कोई वैवाहिक विवाद चल रहा है या नहीं। अगर मामला तय शर्तों के दायरे में आता है तो जांच अधिकारी को पहले पूरे मामले को समझना होगा। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए, जब कानून के मुताबिक उसकी जरूरत हो और आरोपी के अपराध में शामिल होने का जरूरी आधार हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर बच्चे का मूल्यांकन बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा या क्लिनिकल साइकोलॉजी के विशेषज्ञ से कराया जाएगा।

2014 के बाद सबसे ज्यादा दल-बदलू कांग्रेस पार्टी से

नई दिल्ली। भारत में 2014 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में कई बड़े बदलाव आए हैं। फिर चाहे सियासी दलों में नए नेताओं के उभार की बात हो या कुछ नामों के खो जाने की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 से 2021 के बीच हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दो राष्ट्रीय दलों से सबसे ज्यादा सांसद-विधायक दूसरे दलों में चुनाव लड़ने गए। हालांकि, इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। पार्टी से सबसे ज्यादा 177 सांसदों और विधायकों ने दल-बदल किया। यानी सियासी दल छोड़ कर दूसरे दलों से चुनाव लड़ने के लिए जाने वाले सांसद-विधायकों में सबसे ज्यादा कांग्रेस (35.40 फीसदी) के रहे। इस लिस्ट में अगला नंबर भाजपा का है जिसके 33 सांसद-विधायक (करीब 7 फीसदी) पार्टी छोड़ कर दूसरे दलों से चुनाव लड़े। इस बीच अगर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की बात करें, तो भी सबसे ज्यादा 222 उम्मीदवारों (19.59%) ने कांग्रेस और 153 उम्मीदवारों (13.50%) ने बसपा छोड़कर दूसरे दल जॉइन किए और वहां से चुनाव लड़े। इसमें भी एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि चुनाव के बीच कुल 1133 उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ी। इनमें सबसे ज्यादा 253 भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े। यानी कुल संख्या का 22 फीसदी। वहीं, अलग-अलग पार्टी छोड़ने वाले 115 प्रत्याशी (6 फीसदी) कांग्रेस में शामिल हुए। दूसरे दलों के 65 उम्मीदवार (6 फीसदी) चुनाव लड़ने के लिए बसपा में भी आए। सांसद/विधायक- दल बदलकर दोबारा चुनाव लड़ने वाले कुल 500 सांसदों और विधायकों में से 419 यानी करीब 84 फीसदी करोड़पति थे। कुल उम्मीदवार- उधर दल बदलकर चुनाव लड़ने वाले कुल 1,133 उम्मीदवारों में से 706 करोड़पति यानी 62% प्रत्याशी करोड़पति थे।

अजय जम्वाल को अब महाराष्ट्र का प्रभार

भाजपा के कुशल रणनीतिकार अजय जम्वाल का कद पार्टी संगठन में और ऊंचा हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का आधार स्तंभ खड़ा करने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने वाले क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल को अब महाराष्ट्र का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। एनडीए शासित महाराष्ट्र में आगामी राजनीतिक एवं चुनावी समीकरण को साधने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद संकटमोचक पर दांव खेला है। विरासत में मिली राजनीति और संगठन निर्माण कला अजय जम्वाल को राजनीति और संगठन निर्माण की कला विरासत में मिली है। उनके पिता स्व. कर्नल गंगा राम जम्वाल भी भाजपा संगठन में विभिन्न उच्च पदों पर रहे, जबकि उनके छोटे भाई पंकज जम्वाल वर्तमान में प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

गोवा में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सका

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बताया है कि ईसीआईएनईटी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 पर क्लिक करने के बाद उस कार्रवाई को वापस ले सकें। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस सुविधा को चालू करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था। दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान 97 वोटरों को लॉजिकल विसंगतियों के कारण चिह्नित किया गया था, लेकिन बाद में वे अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए। एसआईआर प्रोसेस के दौरान, गोवा में कई वोटर्स को सिस्टम ने लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए चिह्नित किया था। ये गड़बड़ियाँ तब सामने आईं जब वोटर्स को पिछली एसआईआर लिस्ट में उनके माता-पिता या दादा-दादी से जोड़ा जा रहा था। ऐसी गड़बड़ियों के कारण चिह्नित किए गए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। 29 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गोवा में लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए चिह्नित वोटर्स को दस्तावेज़ या आपत्तियाँ जमा करने और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स) के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया गया।

मेघालय में बदल डाला विधानसभा का पूरा गणित

मेघालय की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के आठ विधायक दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही विधानसभा में भाजपा की संख्या बढ़कर दस हो गई और वह सत्तारुढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के बाद सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। क्षेत्रीय दल के इतने बड़े समूह का भाजपा के साथ जाना केवल विधायकों के पाला बदलने की घटना नहीं है, बल्कि यह मेघालय की राजनीति में बदलते समीकरणों और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बढ़ते प्रभाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेघालय की राजनीति लंबे समय से राष्ट्रीय दलों की सीधी प्रतिस्पर्धा से ज्यादा स्थानीय पहचान, जनजातीय हितों और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के इर्द-गिर्द घूमती रही है। खासकर खासी-जैंतिया पहाड़ियों में क्षेत्रीय राजनीति का अपना मजबूत आधार रहा है। यूडीपी इसी राजनीति की प्रमुख धुरी रही है। अब उसी दल के दो-तिहाई विधायक भाजपा में चले गए हैं। मेघालय के स्थानीय मीडिया ने इसे यूडीपी के लिए बड़ा झटका और राज्य के राजनीतिक नक्शे में निर्णायक बदलाव के रूप में देखा है।

आयोग ने जारी की संभावित रिक्तियां, भरीं जाएंगी 10731 वैकेंसी

नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल 2026 की परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले भर्ती की संभावित रिक्तियों का नया आंकड़ा सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 10,731 संभावित रिक्तियां बताई हैं।

यह आंकड़ा उस संख्या से कम है, जो भर्ती की शुरुआत में बताई गई थी। मई 2026 में जारी भर्ती विज्ञापन में आयोग ने संभावित रिक्तियां करीब 12,256 बताई थीं। उस समय आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि रिक्तियां अस्थायी हैं और बाद में इनमें बदलाव हो सकता है। अब जारी संभावित रिक्तियों की सूची में अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में पदों का ब्योरा दिया गया है। नई सूची में 59 पद/विभागीय पद-समूहों के लिए कुल 10,731 रिक्तियां बताई गई हैं। एसएससी सीजीएल 2026 की टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 से शुरू होनी है। परीक्षा अलग-अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए करीब 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

10 हजार मीटर दौड़ में देश को 16 साल बाद मिला पदक

चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रेटा गांव की बेटी सीमा कुमारी ने गुरुवार को एशियन गेम्स के ट्रैक पर इतिहास रच दिया। जापान के आइची नागोया में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में उड़न परी सीमा ने 32 मिनट 50.05 सेकेंड का समय लेकर देश को कांस्य पदक जिता दिया। आखिरी चक्कर तक पदक के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद सीमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। उनकी इस कामयाबी के साथ ही एशियाड में इस स्पर्धा में भारत का 16 साल का पदक का इंतजार खत्म हो गया। एशियन गेम्स में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में भारत को इससे पहले 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने स्वर्ण और कविता राउत ने रजत पदक दिलाया था। एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से शानदार रहा। भारत ने बुधवार को पांच पदक अपने नाम किए, जिसमें एक रजत और चार कांस्य शामिल रहे। इसके साथ ही भारत की कुल पदक संख्या 17 हो गई है। भारत के खाते में अब 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। पांचवें दिन वुशु, मिश्रित 4×400 मीटर रिले, रोइंग, शूटिंग और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते।

सुपरपावर्स की 'डील' से भारत को अलर्ट रहना होगा

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बेहद अहम तीन दिवसीय राजकीय यात्रा की मुख्य द्विपक्षीय वार्ता के लिए बैठेंगे। वाशिंगटन में हो रही इस हलचल पर भारत

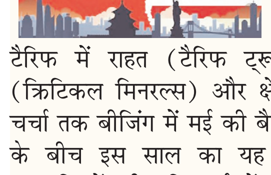

से ज़्यादा सतर्कता शायद ही कोई अन्य देश बरत रहा हो। साउथ लॉन में औपचारिक स्वागत से लेकर एआई गवर्नेंस, टैरिफ में राहत (टैरिफ ट्रूस), महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) और क्षेत्रीय समुद्री विवादों पर चर्चा तक बीजिंग में मई की बैठक के बाद ट्रंप और शी के बीच इस साल का यह दूसरा शिखर सम्मेलन महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में एक बड़ा पड़ाव है। नई दिल्ली के लिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की यह बातचीत बड़े मायने रख सकती है। इन सबके मूल में भारत की चिंता का एक स्थायी कारण है, जिसने दशकों से भारतीय विदेश नीति को परेशान किया है- वह है अमेरिका-चीन के बीच G2 का उदय। इस स्थिति में यह कल्पना की गई है कि वाशिंगटन और बीजिंग एक द्विपक्षीय ढांचा बनाएंगे, जिसके तहत वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों का बंटवारा करेंगे।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए जिस स्तर का राजकीय सम्मान दिखाया गया, उसे देखकर पूरी दुनिया हतप्रभ

अभी तो सिर्फ ट्रेलर सामने आया है, पूरी पिक्चर दिसम्बर में सामने आयेगी

नीरज कुमार दुबे

वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए जिस स्तर का राजकीय सम्मान दिखाया गया, उसे देखकर पूरी दुनिया हतप्रभ है। लेकिन सितम्बर में अमेरिका में दिखी यह कूटनीति सिर्फ ट्रेलर है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है जोकि दिसम्बर में दिखाई जायेगी। वैसे वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का दृश्य मई में बीजिंग में हुए ट्रंप-शी शिखर संवाद की याद दिला रहा है। जिस तरह चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप का भव्य स्वागत किया था और बाद में झोंगनानहाई में स्वयं उनकी अगवानी की थी, उसी तरह अब अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने प्रोटोकॉल से हटकर ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर स्वयं शी जिनपिंग का स्वागत किया। सैन्य बैंड, लाल कालीन, सम्मान गार्ड और लड़ाकू विमान के फ्लाईपास्ट के बीच हुआ यह स्वागत केवल राजकीय औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिका-चीन संबंधों में चल रही कूटनीतिक गर्माहट का बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही करीब छह दशक में किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बेस पर इस तरह की व्यक्तिगत अगवानी असाधारण मानी जा रही है।

देखा जाये तो शी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और चीन के रिश्ते प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच एक नए संतुलन की तलाश में हैं। व्यापार शुल्क, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेदों का कारण बने हुए हैं, लेकिन दोनों पक्ष अब टकराव को नियंत्रित रखने और बातचीत जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। व्यापार युद्ध के बाद बनी अस्थायी व्यापार-समझ को आगे बढ़ाने की कोशिश भी इसी दिशा का संकेत है।

शी जिनपिंग ने भी साफ संकेत दिया है कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी की बजाय साझेदार के रूप में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों

देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक में दोनों के बीच होड़ जारी है, ताइवान का प्रश्न बेहद संवेदनशील बना हुआ है और व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भी मतभेद कायम हैं। इसलिए वॉशिंगटन में हो रही बातचीत को पूर्ण समझौते की बजाय तनाव कम करने और संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत और रूस। दिसंबर में ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। मोदी के दिसंबर में अमेरिका जाने की संभावना है, जहां चौदह और पंद्रह दिसंबर को फ्लोरिडा में होने वाली जी-20 बैठक के दौरान उनकी ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें

वहीं रूस ने अभी पुतिन-ट्रंप दिसंबर शिखर बैठक की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाली जी-20 बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और वहां ट्रंप के साथ मुलाकात की संभावना है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और बैठक के एजेंडे पर चर्चा करना भी जल्दबाजी होगी।

देखा जाये तो इन संभावित मुलाकातों को हाल में नई दिल्ली में संपन्न हुए अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखना खासा महत्वपूर्ण है। भारत की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस स्तर का संवाद और सार्वजनिक गर्मजोशी दिखाई दी, उसने वैश्विक कूटनीति में खासा ध्यान खींचा। मोदी और शी ने द्विपक्षीय संबंधों, सीमा शांति, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, जबकि मोदी और पुतिन ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की।

ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें भी अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संदेश थीं। एक ओर भारत और रूस के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध, दूसरी ओर भारत और चीन के बीच लंबे तनाव के बाद संवाद की वापसी। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण में मोदी, पुतिन और शी की साथ दिखाई देने वाली तस्वीरों को बदलती वैश्विक शक्ति समीकरणों के प्रतीक के रूप में देखा गया।

अतिक्रमण को लेकर जंगल में बवाल

जांच करने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों ने की झूमाझटकी, थाने पहुंचा मामला

गरियाबंद। करका के जंगल में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने टीम को सरकारी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते मौके पर विवाद, धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की स्थिति बन गई। हालांकि गनीमत रही कि घटनाक्रम में किसी वन अधिकारी या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है और मामला किसी बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुआ। वन विभाग की टीम करका क्षेत्र में कथित अतिक्रमित वनभूमि का निरीक्षण और कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विभाग के अनुसार टीम जब कथित अतिक्रमित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शासकीय कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने की कोशिश की गई। विभाग का आरोप है कि इस दौरान ग्रामीण

मुकेश मरकाम को मौके से ले जाया गया। मुकेश की ओर से पूरी घटना की वीडियोग्राफी किए जाने की बात भी विभाग ने कही है। मामले में वीडियो साक्ष्य के साथ थाना खल्लारी में स्न्ढ्ढक्र के लिए आवेदन दिए जाने की जानकारी सामने आई है। करका की मौजूदा कार्रवाई को समझने के लिए इसका पुराना इतिहास भी महत्वपूर्ण है। करका कभी एक वन ग्राम था और सोंढूर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में तत्कालीन सीतानदी अभयारण्य के अंतर्गत आता था। सोंढूर बांध के निर्माण के बाद वर्ष 1980 के दशक में करका गांव का विस्थापन किया गया था। उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के अनुसार करका के 55 व्यक्तियों को जल संसाधन विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया था। इसके बावजूद वन विभाग के अनुसार बाद में इसी क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित वनभूमि पर फिर अतिक्रमण और वन कटाई की गतिविधियां सामने आईं। यानी गांव को हटाने और मुआवजा देने के दशकों बाद भी जंगल की जमीन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ। 22 सितंबर 2026 को किए गए मैदानी निरीक्षण में वन विभाग को 1,100 से ज्यादा पेड़ों पर गर्डलिंग और बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों के ठूंठ मिले। विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार वर्ष 2016 से 2017 के बीच करीब 30 हजार पेड़-पौधे काटे जाने के संकेत मिले हैं। त्रक्क-आधारित आकलन में लगभग 35 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण के संकेत मिले हैं। हालांकि विभाग के अनुसार अंतिम क्षेत्रफल का निर्धारण ष्ठत्रक्क-आधारित ड्रोन मैपिंग पूरी होने के बाद किया जाएगा। वर्ष 2016 में भी करका से जुड़े 22 व्यक्तियों के खिलाफ करीब 22 हेक्टेयर घने वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर क्कह्रक्र दर्ज किया गया था। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नगरी न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। अब वन विभाग सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन फुटेज, त्रक्क/ष्ठत्रक्क मैपिंग और मैदानी साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्र की स्थिति का दोबारा आकलन कर रहा है।

आदिवासी बाहुल्य जशपुर में तैयार हुआ क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक

16.67 करोड़ की लागत से जशपुर में 50 बिस्तरों की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक तैयार किया गया है।

जशपुरनगर। आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल धरातल पर आकार ले चुकी है। जिले में 16.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा 50 बिस्तरों की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अब लगभग तैयार हो गया है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और इन दिनों वायरिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अस्पताल के संचालन के लिए आवश्यक चिकित्सकीय एवं कार्यालयीन स्टाफ की नियुक्ति और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के शुरू होने के बाद जशपुर जिले के गंभीर मरीजों को उपचार के लिए रायपुर, रांची, राउरकेला सहित दूसरे बड़े शहरों और पड़ोसी राज्यों की ओर जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो सकेगी। गंभीर बीमारी, सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे मामलों में मरीजों को जिले के भीतर ही

आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीएस जात्रा ने बताया कि क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से इस परियोजना के लिए 16.67 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में वायरिंग सहित कुछ आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए चिकित्सकीय और कार्यालयीन स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने के बाद आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक सामान्य अस्पताल की तरह संचालित नहीं होगा। यहां नियमित ओपीडी के बजाय गंभीर मरीजों और आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. जात्रा के अनुसार, जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों से गंभीर बीमारी या दुर्घटना में घायल मरीजों को यहां तत्काल और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रस्तावित है। इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए छह विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 मेडिकल ऑफिसर और करीब 60 नर्सों की व्यवस्था की जानी है। पर्याप्त चिकित्सकीय मानव संसाधन उपलब्ध होने के बाद अस्पताल की सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भवन तीन मंजिला है। इसमें मरीजों की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचार की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

धर्मांतरण के लिए सैकड़ों आवेदन, क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी का दावा

धमतरी। चर्च में आराधना के लिए प्रवेश केवल ईसाइयों के लिए है। अन्य यदि स्वेच्छा से आते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये बोर्ड धमतरी के 116 साल पुराने ऐतिहासिक मेनोनाइट सुंदरगंज चर्च के गेट के पास लगा है। जिले के करीब 35 से 40 चर्च और प्रार्थना सभा स्थलों पर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। प्रार्थना सभाओं और धर्म परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच चर्च और प्रार्थना सभा स्थलों के बाहर लगाए गए प्रवेश संबंधी बोर्ड चर्चा में हैं। धमतरी क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी डायमंड फिलस का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ संगठनों की ओर से चर्चों में गैर-ईसाइयों के प्रवेश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक कई बार प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबे और विरोध की स्थिति बनने से समाज की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं। डायमंड फिलस ने कहा कि सुरक्षा और प्रार्थना सभाओं के दौरान होने वाले कथित विवादों को रोकने के लिए चर्च के बाहर

ऐसे बोर्ड लगाए गए। फोरम के जनरल सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि चर्च में किसी दूसरे समाज के लोगों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ना ही शासन ने कोई प्रतिबंध लगाया और ना ही मसीही समाज ने किसी तरह की रोक लगाई है। गैर ईसाइयों के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ प्रार्थना सभा में शामिल होना चाहता है तो वह आ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। यदि कोई संगठन, शासन प्रशासन की तरफ से पूछताछ होती है तो इसका जवाब मसीही समाज की तरफ से नहीं दिया जाएगा, संबंधित व्यक्ति जवाब देने के लिए जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चर्च ईसाइयों की आराधना का स्थान है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौजूद है। अपने तर्क के लिए उन्होंने दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग भी श्रद्धा से दरगाह जा सकते हैं, उसी तरह कोई व्यक्ति सम्मान के साथ चर्च में भी आ सकता है। धर्म परिवर्तन को लेकर फोरम का दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रशासन के पास करीब ढाई से तीन सौ आवेदन लंबित है। डायमंड फिलस के अनुसार, ये आवेदन उन लोगों से जुड़े हैं जो स्वयं को ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा रखने वाला बताते हुए प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चर्च में आने या प्रार्थना करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक कुछ लोगों की व्यक्तिगत आस्था के चलते धर्म परिवर्तन की इच्छा हो सकती है और इसी वजह से वर्ष 2025 से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू होने तक कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन संबंधी घोषणा या आवेदन जमा किए हैं।

मानिकपुर खदान विस्तार : भूविस्थापितों ने उठाई पुरानी मांगों के समाधान की मांग

कोरबा। मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित 8 गांवों के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जनरल मैनेजर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। इसके बाद बुधवार शाम को टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भूविस्थापितों ने पुरानी समस्याओं का समाधान किए बिना जनसुनवाई के आयोजन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एसईसीएल लगातार उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अब तक यह स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने मकानों को तोड़ने का मूल्यांकन हुआ है। कितना मुआवजा मिलेगा। कुछ मांगे तो 1964 से लेकर अब तक लंबित है। भूमि स्थापित संगठन की ओर से प्रेस वार्ता में मौजूद अमन पटेल का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं बल्कि उनका विरोध दशकों पुराने लंबित अधिकारों और न्यायोचित समाधान के बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर है। ?1963-64 में मानिकपुर क्षेत्र के कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थीं। इतने साल बीत जाने के बाद भी कई प्रभावित परिवार मुआवजा, विस्थापन के बाद रोजगार और पुनर्वास जैसे मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्व में 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई विरोध के बाद स्थगित हो गई थी। जिसके बाद अब 25 सितंबर 2026 की नई तारीख निर्धारित की गई है। सवाल यह है कि जब तक पुरानी समस्याएं लंबित हैं, तब तक नई जनसुनवाई को केवल एक औपचारिक प्रक्रिया क्यों बनने दिया जाए। जनसुनवाई से पहले लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई और समयबद्ध कार्ययोजना सामने आनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थायी रोजगार के मामलों के समाधान से पहले निजी ठेका कंपनियों के माध्यम से रोजगार की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो कि मात्र दिखावा प्रतीत होती है। इसके अलावा, काम कर रहे युवाओं और वाहन चालकों की सुरक्षा राशि, लाइसेंस व अन्य शर्तों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है, ताकि किसी का आर्थिक शोषण न हो। ग्रामीणों ने भिलाईखुर्द, दर्रीपारा और कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग के पास स्थित बंजरंग चौक के आसपास धूल, राखड़ के गुबार और पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभावों का मुद्दा उठाया है।

दो करोड़ की सड़क उखड़ने का मामला

पीएमजेसीवाय विभाग ने आरोपों को किया खारिज, सड़क को बताया बेस्ट

कबीरधाम। कबीरधाम के चिमरा मेन रोड से बरभांवर तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत हुआ था।लेकिन अब इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में कांग्रेस के नेताओं ने सड़क निर्माण में खामी बताते हुए इसे हाथ से उखाड़कर दिखाया था।जिस पर अब क्करूत्रस्ङ्घ विभाग के अधिकारी का बयान आया है।अधिकारी ने सड़क को गुणवत्ताहीन मानने से इंकार किया है। आरोप है कि जानबूझकर सड़क को क्षति पहुंचाई गई और फिर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। सड़क उखड़ने का वीडियो सामने आने के बाद जब मौके का निरीक्षण किया गया तो सड़क अच्छी हालत में मिली।सड़क निर्माण के दौरान जो भी मानक तय किए गए थे।चाहे वो बिटुमिन की थिकनेस हो या अन्य चीजें सारे मानकों को फिर से जांचा

गया।ये सारे मानक सही पाए गए।सड़क की गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नही है। विकास कौशिक की माने तो जिस जगह पर सड़क को उखाड़ा गया है उसे जानबूझकर तोड़ा गया है। ऐसा किसने किया है इसे लेकर हम जांच कर रहे हैं।सड़क उखाड़ने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दो दिन पहले कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ सड़क की डामर की परत को हाथों से उखाड़ते नजर आए थे। कांग्रेस नेता तुकाराम चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है और सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सड़क की डामर की परत हाथ से उखड़ती दिखाई दे रही है, तो विभागीय जांच में सड़क की गुणवत्ता सही कैसे पाई गई? क्या सड़क की जांच के दौरान निर्माण की गुणवत्ता के तकनीकी मानकों की पर्याप्त जांच हुई या महज औपचारिकता पूरी की गई?। आपको बता दें कि इसी विभाग की एक अन्य सड़क की गुणवत्ता को लेकर कुछ दिन पहले भी सवाल उठे थे। खबर सामने आने के बाद विभागीय सचिव ने मौके पर पहुंचकर जांच कराई थी और संबंधित इंजीनियर को निलंबित करने समेत ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में चिमरा-बरभांवर सड़क को मिली कथित क्लीन चिट ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की स्वतंत्र तकनीकी जांच और निर्माण सामग्री के सैंपल की लैब जांच कराई जाए, ताकि सामने आ सके कि सड़क की वास्तविक गुणवत्ता क्या है और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार कौन है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कैदी जसबीर कौर जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार

दुर्ग। जिले की चर्चित लेडी डॉन जसबीर कौर एक बार फिर पुलिस और जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गई। जसबीर कौर ने बुधवार को बच्चे के इलाज का बहाना बनाया और दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचीं, जहां वह सुरक्षाकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर भागने में कामयाब रहीं। हालांकि किसी तरह पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे फिर गिरफ्तार कर लिया है। जसबीर कौर हेरोइन तस्करी के आरोप में 19 सितंबर को जेल भेजी गई थी। इसके बाद उसने बच्चे के इलाज का बहाना बनाया था। उसके फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया उसकी तलाशी ली गई। शातिर महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी करते हुए महज एक घंटे के अंदर जसबीर कौर को दोबारा अस्पताल परिसर से ही धर दबोचा। वापस सलाखों के भीतर पहुंचाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जसबीर के कारनामों की वजह से दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। फिलहाल जसबीर कौर फिर से सलाखों के पीछे हैं।

इनोवा कार से कर रहे थे तस्करी, 81.20 लाख का माल जब्त

पिथौरा। महासमुंद जिले में पुलिस और एएनटीएफ की टीम द्वारा गांजा की तस्करी, परिवहन और बिक्री पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक इनोवा कार से 66 लाख का गांजा बरामद किया है और दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला बसना थाना क्षेत्र का है। पुलिस और ्ट्रहृञ्जस्न की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे से भरी एक इनोवा कार ओडिशा की ओर से आ रही है, जिसके बाद टीम ने नाकाबंदी कर इनोवा कार क्रमांक एमएच 04 जीएम 8841 को रोका और तलाशी लेने पर उसमें से 132 किलो गांजा बरामद हुआ।इसके साथ ही पुलिस ने गणेश बाजे पिता रामदास बाजे (42), निवासी पिपलवंडी, जिला पुणे, महाराष्ट्र और विपुल पिता रामचंद्र भालेराव (36), निवासी कलंब, जिला पुणे, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ओड़िशा के तुमुड़ीबंध (कंधमाल) से यह गांजा लेकर पुणे (महाराष्ट्र) ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

डिजिटल स्क्रीन पर 12 ज्योतिर्लिंग, चारधाम के दर्शन

भिलाई दुर्ग। भिलाई के सेक्टर 10 का प्रसिद्ध गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिवमानस गणेश उत्सव समिति द्वारा तैयार इस पंडाल में इस बार धार्मिक आस्था के साथ तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। करीब 4 हजार वर्ग फीट की डिजिटल स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। केदारनाथ और मां दंतेश्वरी की थीम पर तैयार यह डिजिटल 3ष्ठ इल्यूजन पंडाल श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव दे रहा है, मानो वे एक साथ देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों की यात्रा कर रहे हो। पंडाल में प्रवेश करते ही डिजिटल स्क्रीन पर बदलते दृश्य श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। विशाल स्क्रीन पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और ज्योतिर्लिंगों की झलक दिखाई जाती है। 3ष्ठ इल्यूजन तकनीक के जरिए तैयार किए गए इन दृश्यों में श्रद्धालुओं को अलग-अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन का अनुभव कराया जा रहा है।

मां ने पढ़ने के लिए डांटा तो बच्चा पहुंचा मायानगरी मुंबई

सूरजपुर। गार्जियन अक्सर बच्चों को पढ़ने के लिए डांटते रहते हैं। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अपना जीवन बेहतर बनाए। कई बार बच्चों को माता-पिता की प्यार भरी फटकार नागवार गुजरती है। ऐसे में कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र में। यहां 9 साल का बच्चा मां की फटकार से नाराज होकर घर से भाग गया। बच्चा किसी तरह से स्टेशन तक पहुंचा और दो से तीन ट्रेन बदलने के बाद मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जब अपने घर नहीं पहुंचा तो माता-पिता को उसकी चिंता हुई। परिजनों ने पहले से बच्चे को आस-पास खोजा फिर स्कूल जाकर उसका पता लगाया। लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तब परिजनों का माथा ठनका। बच्चे के परिजन बच्चे की फोटो लेकर पुलिस थाने पहुंचे। परिजनों ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि बच्चा जब नाराज होकर घर से निकला था तो ये कहकर गया था ।

सनरूफ और चारों दरवाजे खोलकर हाईवे पर स्टंट

अम्बिकापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सनरूफ और दरवाजे खोलकर खतरनाक तरीके से कार चलाकर स्टंटबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया और अखबारों में वीडियो व तस्वीरें वायरल होने के बाद बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 19 सितंबर 2026 की है। थाना बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर स्थित नगर सेना तिराहा (सेमली) के पास एक एक्सयूवी का चालक अपने चार अन्य साथियों के साथ खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। वाहन चालक सुनील गुप्ता (निवासी ग्राम अधौरा, थाना बलरामपुर) ने कार के चारों दरवाजे और सनरूफ खोल रखे थे, जिससे सवार युवक बाहर निकलकर हुड़दंग मचा रहे थे। इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना स्टंट से न केवल कार सवारों की जान जोखिम में थी।

कोरबा में समृद्धि मल्टी लेवल पार्किंग बना सफेद हाथी

करोड़ों खर्च के बाद भी उपयोगिता शून्य, अब भी शहर में लगता है जाम

कोरबा। शहर के मुख्य मार्गों पर बढ़ते यातायात समस्याओं के समाधान और सुगम आवागमन के दावे के साथ बनाई गई करोड़ों की आधारभूत संरचनाएं सफेद हाथी साबित हो रही है। शहर के पावर हाउस रोड के समीप 17 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से तैयार तीन मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। यह शहर में एक %सफेद हाथी% साबित हो रहा है। स्थिति यह है कि इस भव्य इमारत में वाहनों की पार्किंग शून्य के बराबर है। ?इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 2018-19 से पावर हाउस रोड के पास ओवरब्रिज के समीप शुरू किया गया था। शुरुआती दौर

से ही यह प्रोजेक्ट प्रशासनिक अड़चनों, फंड की कमी और तकनीकी बहसों में उलझा रहा। निर्माण कार्य लंबे समय तक बंद भी रहा, जिससे इसकी उपयोगिता और औचित्य पर लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि, तमाम विवादों और देरी को पार करते हुए हाल ही में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और इसी वर्ष जुलाई महीने में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि इससे शहर के व्यस्त इलाकों में वाहन पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत निकली। इस मल्टी-लेवल पार्किंग की सबसे बड़ी विफलता इसका स्थान है, यह पार्किंग मुख्य बाजार और कॉमर्शियल हब से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय वाहन चालकों और खरीदारों का कहना है कि बाजार से दूर गाड़ी पार्क करने के बाद लंबी दूरी तय कर पैदल मार्केट तक जाना व्यावहारिक नहीं है, खासकर तब जब लोग सामान की खरीदारी करने निकलते हैं। जानकारों और स्थानीय नागरिकों का मानना है कि जब इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तभी इसके लोकेशन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन जनभावनाओं और व्यावहारिक पहलुओं को दरकिनार कर इस पर भारी-भरकम बजट झोंक दिया गया। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन का कहना है कि मल्टी लेवल पार्किंग शहर के लिए उपयोगी तो है लेकिन पावर हाउस रोड से दूरी अधिक होने के कारण लोग यहां तक पैदल चलकर नहीं जाना चाहते। कोरबा शहर में पैदल चलने का कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, लोग दुकान के बाहर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं। दुकान से सामान लेते हैं।

बैरक से रसोई और स्वास्थ्य केंद्र तक जांच

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सहायक जेल अधीक्षक से बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, खाद्य सामग्री, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण दल ने जेल के भोजनालय में बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और चिकित्सा सेवाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जेल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था और बंदियों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। बंदियों को उनके विधिक अधिकार, जमानत की प्रक्रिया और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई।पात्र बंदियों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि जेल में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अपने

कानूनी अधिकारों की जानकारी हो और जरूरत पड़ने पर उसे उचित विधिक सहायता मिल सके। सिरसा में उपायुक्त व एडीसी ने चखा जेल का खाना, जिला कारागार में जेल रेडियो, लाइब्रेरी और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र करवाया शुरू निरीक्षण के दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता शिल्पा दांडेकर, दीपेश भारती, एसडीओ राकेश डांडी, डीटीआईसी चंचल श्रीवास्तव, डीपीएस कंवर, सहायक जेल अधीक्षक अमितेश साहू सहित जेल का स्टाफ मौजूद रहा।

संक्षिप्त समाचार

नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी भगत का पहला छत्तीसगढ़ दौरा 27 से

रायपुर। लोकसभा सांसद सुखदेव भगत

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार 27 सितंबर को प्रदेश आ रहे हैं। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों, संगठनों एवं विभागों प्रमुखों के अलावा कनेक्ट सेंटर टीम के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं के साथ वन-टू-वन भी बैठक करेंगे। सुखदेव भगत के आगमन को देखते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। धरसीवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष वर्मा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी भगत के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर उनके ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही हैं।

स्मृति ईरानी को भाजपा के प्रभारी बनाए जाने पर भूपेश बघेल ने कसा तंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई जिम्मेदारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रभारी बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने स्मृति ईरानी को चोट खाई हुई और घायल शेरनी बताते हुए कहा है कि अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ आने के बाद वह किसे हटाती हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी का वनवास खत्म हुआ है। चोट खाई हुई स्मृति ईरानी हैं, घायल शेरनी हैं। यहां आने के बाद किसको हटाती हैं, यह देखना होगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी चर्चा तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी के पुराने चुनावी मुद्दों का जिक्र करते हुए गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठी थीं और मोदी गारंटी के तहत 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही गई थी। बघेल के इस बयान को बीजेपी की चुनावी गारंटियों और महंगाई के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है।

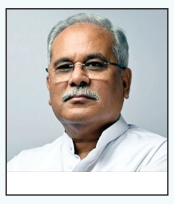

29 सितंबर की रात से बंद होगा उरकुरा रेलवे फाटक

रायपुर। रेलवे प्रशासन की ओर से मांढर-

उरकुरा स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक 414 पर जरूरी तकनीकी कार्य के चलते उरकुरा रेलवे फाटक 29 सितंबर की रात 10 बजे से बंद किया जाएगा। यह कार्य पूरा होने तक फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे के अनुसार, कार्य सामान्य परिस्थितियों में 30 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे तक पूरा होने की संभावना है। मांढर-उरकुरा रेलवे स्टेशनों के बीच समपार क्रमांक 414 किलोमीटर क्षेत्र में नई रेलवे लाइन से संबंधित कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे ट्रैक पर चेक रेल लगाने का काम किया जाएगा। इस कार्य के दौरान कर्मचारियों और मशीनरी की आवाजाही तथा तकनीकी कार्य के लिए फाटक को बंद रखना आवश्यक होगा। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि 29 सितंबर की रात 10 बजे के बाद इस फाटक से आवागमन की योजना न बनाएं और जरूरत पडने् पर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।

दूध नदी पर पुल और पहुंच मार्ग के लिए 16.15 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने कांकेर जिले में दूध नदी पर पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 16 करोड़ 14 लाख 71 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से कोदाभाठ-माटवाड़ा मोदी मार्ग पर दूध नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति का पत्र प्रमुख अभियंता को जारी कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कर्मवीर छत्तीसगढ़ में प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाए गए

■ **आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा के साथ छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) बने शिवप्रकाश**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। जिसके तहत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा के साथ छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) का दायित्व शिवप्रकाश को दिया है जिनका केंद्र मुंबई होगा। अब तक छत्तीसगढ़, मप्र के क्षेत्रीय महामंत्री रहे अजय जम्वाल मुक्त कर दिए गए हैं, उन्हें महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी सम्हाल रहे पवन साय को हटाकर झारखंड भेज दिया गया है वहीं छत्तीसगढ़ का जिम्मा कर्मवीर संभालेंगे और उनका केंद्र रायपुर रहेगा। इससे पहले कर्मवीर झारखंड में प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे थे।

छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कर्मवीर सिंह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला वर्तमान में अब हाथरस जिला के स्वयंसेवक है। 1993 से संघ के प्रचारक जीवन का प्रारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली से किया इसके बाद तहसील प्रचारक, नगर प्रचारक रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी (आगरा) व अलीगढ़ महानगर प्रचारक एवं मथुरा जिला के जिला प्रचारक बने। उत्तर प्रदेश के एटा, अलीगढ़ व बरेली विभाग के विभाग प्रचारक रहे। 2015 में मेरठ प्रांत (पश्चिम उत्तर प्रदेश) के सह प्रांत प्रचारक बने। 2019 में ब्रज प्रांत के सह प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किया। 2020 से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सह महामंत्री (संगठन) के रूप में कार्य किया। अगस्त 2022 से आपकी योजना झारखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री (संगठन) के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मवीर का केन्द्र भाजपा प्रदेश कार्यालय, रांची (झारखंड) है।

रायपुर में अब 14 जगहों पर होगी रजिस्ट्री की सुविधा

रायपुर। राजधानी रायपुर में जमीन, मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। शासन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पांच नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। ये कार्यालय आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से भी लैस होंगे। इनके शुरू होने के बाद रायपुर में कुल 14 स्थानों पर जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी में 7 रजिस्ट्री कार्यालय हैं जिनपर भीड़ का दबाव काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में रजिस्ट्री के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ जाता है। वहीं दो दफ्तर बेबीलॉन टॉवर और विधानसभा रोड स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क में पहले ही खुल चुके हैं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले रायपुर के पंजीयक कार्यालय में रोजाना 400 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री होती थी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण मुख्य रजिस्ट्री कार्यालय में लगातार भीड़ बनी रहती है। इसे देखते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब यहां औसतन 150 रजिस्ट्रीयां होती हैं। नए रजिस्ट्री केंद्र मुख्य रूप से शहर के आउटर इलाकों में खोले जाएंगे। इसके लिए भवन तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाटीबंध-हीरापुर, अमलीडीह-अवंति विहार और बीरगांव-सिलतरा समेत आउटर क्षेत्रों में नए केंद्र खोले जाने की तैयारी है इससे इन क्षेत्रों के लोगों को अपने नजदीक ही रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। नए भवन आधुनिक सुविधा से लैस होंगे। जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।

वर्तमान में जिले के दूर-दराज के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए रायपुर समेत अन्य क्षेत्रों के दफ्तर में जाना पड़ता है। नए कार्यालय खुलने से लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्र में सुविधा मिल जाएगी। कलेक्टोरेट परिसर में नई पांच मंजिला पंजीयन बिल्डिंग का आगामी कुछ महीनों में लोकार्पण होना है। रायपुर जिला पंजीयक विनोज कोचे ने बताया कि इस बिल्डिंग में पंजीयक के अलावा 8 उपपंजीयक बैठेंगे। वहीं अन्य सभी उपपंजीयक दफ्तरों में 1-1 उपपंजीयक बैठेंगे। इस तरह शहरी क्षेत्र में कुल 15 उपपंजीयक अपनी सेवाएं देंगे।

बच्चों के मध्यान्ह भोजन पर संकट रसोईया संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईया महिलाओं की परेशानी अब आंदोलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। नीलू ओगरे के आरोप के मुताबिक, 16 जून से अब तक रसोईया बहनों को मानदेय नहीं मिला है। वहीं समूह संचालक भी भुगतान नहीं होने से परेशान हैं।संगठन ने अब 28 सितंबर तक भुगतान की डेडलाइन दी है।

मध्यान्ह भोजन रसोईया संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे का आरोप है कि स्कूल खुलने के बाद 16 जून से लगातार काम करने के बावजूद रसोईया महिलाओं को तीन महीने का मानदेय नहीं मिला है। उनका कहना है कि कम मानदेय पर काम करने वाली रसोईया महिलाओं के लिए समय पर भुगतान बेहद जरूरी है, लेकिन भुगतान लंबित होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

नीलू ओगरे ने कहा 11 सितंबर को डीपीई मंत्रालय से राशि का आबंटन जारी किया जा चुका है, लेकिन 23 सितंबर तक रसोईया महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंची। संगठन की ओर से इस देरी को लेकर सवाल उठाया गया है कि जब राशि आबंटित हो चुकी है, तो भुगतान खातों तक पहुंचने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है।

मानदेय के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन सामग्री की राशि को लेकर भी परेशानी सामने आने का दावा किया गया है।नीलू ओगरे के अनुसार, समूह संचालकों के खातों में राशि नहीं आने से उन्हें मध्यान्ह भोजन की सामग्री खरीदने में दिक्कत हो रही है।समूह संचालकों का सवाल है कि जब खाते में पैसा नहीं है, तो लगातार सामग्री की व्यवस्था कैसे की जाए।

भुगतान को लेकर संगठन ने अब स्पष्ट चेतावनी दी है। नीलू ओगरे के मुताबिक, 28 सितंबर 2026 तक रसोईया और समूह संचालकों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो रसोईया हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकती हैं।यानी अब सरकार और शिक्षा विभाग के सामने सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है। भुगतान हुआ तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर राशि नहीं पहुंची तो आंदोलन की स्थिति बन सकती है।

संगठन की मांग है कि रसोईया महिलाओं का पिछले तीन महीने का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए।। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन सामग्री के लिए समूह संचालकों के खातों में राशि जमा की जाए, ताकि स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो।

रास गरबा में रेंट पर पार्टनर के विज्ञापन पर फूटा गुस्सा

कन्हैया के नेतृत्व में सौंपा गया पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन

रायपुर। हिंदू धर्म के पावन पर्व नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले रास गरबा में रेंट पर पार्टनर उपलब्ध कराने संबंधी सोशल मीडिया विज्ञापन को लेकर जनाक्रोश भड़क गया है। इस गंभीर मुद्दे पर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि जगत जननी मां जगदंबे की आराधना का पर्व नवरात्रि अत्यंत पवित्र और आस्था का प्रतीक है। ऐसे पावन अवसर पर रास गरबा के लिए %रेंट पर पार्टनर' का पोस्टर जारी कर विज्ञापन करना सनातन धर्म का अपमान है और इससे माँ दुर्गा के उपासकों व समस्त सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। कन्हैया अग्रवाल ने शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि कुछ इवेंट कंपनियां लगातार धार्मिक आयोजनों को टारगेट कर सामाजिक मर्यादाओं को तार-तार कर रही हैं। भविष्य में कोई भी संस्था या इवेंट कंपनी इस तरह का दुस्साहस न कर सके, इसके लिए ऐसे असामाजिक तत्वों और आयोजकों पर गैर-जमानती धाराओं के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि इससे पहले भी न्यूड पार्टी और रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर महिलाओं के लिए पैग फ्री जैसे अनैतिक विज्ञापन जारी कर शासन-प्रशासन को चुनौती दी जा चुकी है। ऐसी प्रवृत्तियों पर समय रहते लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक, सुरेश बाफना, आस मोहम्मद, शरद गुप्ता, देवेंद्र पवार, शंकर सेन, राजेश त्रिवेदी, प्रतीक तिवारी, सैफुल्लाह, जी. करणराज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

आज से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, 27 को निकलेगी झांकी

■ **तालाबों में नहीं होगा विसर्जन,किया तो कटेगी चालान**

रायपुर। 25 सितंबर से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जायेगा। महादेवघाट में बड़ी प्रतिमाएं विसर्जित होंगी, जबकि छोटी प्रतिमाओं के लिए शहर में 43 जगह अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। तालाबों में प्रतिमा विसर्जित करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। खारून नदी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब समेत अन्य तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। अब तक महादेव घाट के विसर्जन कुंड में 200 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है।इसके बाद 27 सितंबर को शहर में झांकियां निकाली जाएंगी, जिसे लेकर पुलिस ने ट्रैफिक रूट जारी कर दिया है। समिति वालों के साथ हुई प्रशासनिक बैठक के बात ये भी तय हो गया है कि सदर वाली रूट से ही झांकी निकलेगी लेकिन डीजे नहीं बजेगा,सीमति साउंड सिस्टम के साथ झांकी निकाली जायेगी। अब देखना ये हैं कि इसका कितना पालन हो पाता है।

नगर निगम ने महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड की व्यवस्था संभालने के लिए समिति गठित की है। यहां 25 सितंबर सुबह 6 बजे से 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खारून नदी, तेलीबांधा तालाब और बूढ़ातालाब समेत अन्य तालाबों में प्रतिमा विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

गणेश विसर्जन और झांकियों को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का प्लान तैयार किया है। बुधवार को सी-4 भवन में गणेश उत्सव समितियों के आयोजकों की बैठक हुई, जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और एसडीआरएफ के अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

विसर्जन के दौरान शहर में 1 हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पुलिस ने समितियों से निर्धारित विसर्जन स्थल का ही उपयोग करने की अपील की है। समितियों ने साउंड सिस्टम तय मानक के अनुसार रखने, बेस और वाइब्रेशन मोड बंद रखने पर सहमति दी है।

नगर निगम ने महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड की व्यवस्था संभालने के लिए समिति गठित की है। यहां कल (25 सितंबर) सुबह 6 बजे से 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खारून नदी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब समेत अन्य तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। अब तक महादेव घाट के विसर्जन कुंड में 200 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है।

स्टाफ बस में आग: मंत्रालय कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

रायपुर। नवा रायपुर में मंत्रालय स्टाफ बस में आग लगने की घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुए और बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सभी स्टॉफ बसों की फिटनेस और तकनीकी स्थिति की जांच कराने की मांग की है।

कर्मचारियों का आरोप है कि स्टाफ को लाने-ले जाने वाली ज्यादातर बसें पुरानी और कंडम हो चुकी हैं, जिसको लेकर पहले भी कई बार अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। कई बार मंत्रालय जाते समय बस रास्ते में चार से पांच बार तक बंद हो जाती थी। कर्मचारियों का कहना है कि अगर संभव हो तो नई बसें उपलब्ध कराई जाएं या फिर मौजूदा बसों की नियमित रूप से फिटनेस और तकनीकी जांच सुनिश्चित की जाए। वहीं, घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी के गठन की बात सामने आई है। कर्मचारियों का कहना है कि बस में आग लगने की घटना पहली बार नहीं है। संघ की ओर से लगातार अधिकारियों को बसों की स्थिति से अवगत कराया जाता रहा है। इन बसों में पहले भी छोटी-मोटी घटनाएं होती रही हैं और इसकी जानकारी अधिकारियों के संज्ञान में थी। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि परिवहन विभाग की ओर से बसों की फिटनेस जांच की जाती है, लेकिन यह जांच सिर्फ नाममात्र की है या वास्तव में बसों का तकनीकी परीक्षण किया जाता है।

वित्तमंत्री ने खर्राघाट में 29.99 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'सेवा मेरा योगदान' पहल के तहत रायगढ़ में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और शहरी अधोसंरचना विकास को एक साथ जोड़ते हुए केलो नदी तट के स्थायी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने गुरुवार को खर्राघाट में 29.99 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के साथ स्वच्छता अभियान में स्वयं श्रमदान कर जनभागीदारी का संदेश दिया। परियोजना के तहत शनि मंदिर से खर्राघाट तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र का विकास करने के साथ खर्राघाट में लगभग 8.50 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजोन विकसित किया जाएगा।

सेवा मेरा योगदान के तहत खर्राघाट और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने स्वयं श्रमदान करते हुए कहा कि स्वच्छता किसी एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की निरंतर जिम्मेदारी है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से केलो नदी, घाटों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान किया।

इस दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने केलो नदी में डुबकी लगाकर नदी को नमन किया। उन्होंने कहा कि केलो नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि रायगढ़ की पहचान, आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी भावना के साथ नदी और इसके तटों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए स्थायी विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि खर्राघाट का विकास केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। इसे ऐसा सुव्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां नागरिकों को प्रकृति के बीच बेहतर वातावरण के साथ स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं भी मिल सकें। यहां ऑक्सीजोन, सुव्यवस्थित घाट, पैदल पथ, व्यायाम की सुविधाएं तथा मॉर्निंग और नाइट वॉक के लिए बेहतर स्थान विकसित किए जाएंगे। परिवारों के साथ समय बिताने के लिए भी सुविधाजनक सार्वजनिक क्षेत्र तैयार होगा।

उन्होंने बताया कि खर्राघाट से शनि मंदिर की दिशा में आगे मरीन ड्राइव विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में केलो नदी तट का सुव्यवस्थित और चरणबद्ध विकास हो सकेगा।

परियोजना के अंतर्गत शनि मंदिर से खर्राघाट पुल तक करीब 2 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। सड़क के साथ नाली निर्माण, पैदल पथ और नदी तट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पचरी घाट का नवीनीकरण एवं सुधार होगा तथा घाट को पाथवे से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा। शनि मंदिर के पास तिराहे का चौड़ीकरण कर यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा।

खर्राघाट में करीब 8.50 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजोन विकसित होगा। यहां सघन पौधरोपण के साथ पार्किंग, पाथवे, घाट तथा व्यायाम और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऑक्सीजोन और घाट के बीच सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पुल के नीचे अंडरपास यानी बॉक्स कल्वर्ट भी बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में गार्डन और ऑक्सीजोन विकसित किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधनं विभाग, कार्यालय मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)

ई. प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://cproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 199661/निविदा सूचना क्र. 02/व.ले.लि./2026-27 दि. 21.09.2026 निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 12.10.2026 17.30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नाम - बीजापुर जिले के विकासखंड भैरमगढ़ के मिरतुर तालाब का जीर्णोद्धार एवं 03 नग व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत - **रू, 301.87 लाख (जी.एस.टी. छोड़कर)**

(एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 से प्रचलित (यथा संशोधित दिनांक 08.08.2025))

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 28.09.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस निविदा में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2026 तक है, वह लागू होगी।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग बीजापुर
कृते मुख्य अभियंता गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग जगदलपुर छ.ग.

जी-262703456/10

निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं पंजाब विस चुनाव

अश्वनी कुमार

अगले वर्ष के आरंभ में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव राज्य के उथल-पुथल भरे राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, आगामी चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तौर-तरीकों और समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार पांच प्रमुख राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनावी मैदान में आमने-सामने होंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को चुनौती देने वाले चार विपक्षी दलों में 'वारिस पंजाब दे' भी शामिल है। यह एक नवोदित राजनीतिक संगठन है, जिसने अपने सुधारवादी तेवर और राजनीतिक बदलाव के वादे के कारण ग्रामीण सिख युवाओं के बीच उल्लेखनीय समर्थन हासिल किया है। यह स्थिति पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति घटती जन-रुचि का भी संकेत देती है। राजनीति की एक रोमांटिक और आदर्शवादी कल्पना से काफी हद तक अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाला यह नया राजनीतिक दल अन्य दलों, विशेषकर अकाली दल, के मत प्रतिशत में सेंध लगा सकता है, हालांकि संभवतः वह सत्तारूढ़ दल के लिए गंभीर चुनौती पेश करने की स्थिति में न हो। फिर भी, चुनावी मैदान में इसकी स्पष्ट उपस्थिति ने पंजाब के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया है और उग्र राजनीति की वापसी को लेकर आशंकाओं को फिर से जन्म दिया है। राजनीतिक प्रासंगिकता पुन: हासिल करने का प्रयास कर रहे अकाली दल का कमजोर होता प्रभाव, तेजी से उभरती भाजपा और कांग्रेस द्वारा स्वयं को पहुंचाए गए राजनीतिक नुकसान-इन सभी ने मिलकर पंजाब की राजनीति को बदल दिया है। इसके साथ ही, अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है और यह गठबंधन 'आप' के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में उभर सकता है। इन परिस्थितियों में, खंडित जनादेश और उससे पैदा होने वाली राजनीतिक अस्थिरता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जमीनी परिस्थितियां और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की आवश्यकताएं राजनीतिक संवाद में शालीनता तथा आपसी संबंधों में मर्यादा और सौहार्द की वापसी की मांग करती हैं। राजनीतिक नेताओं के बीच संवाद के सौहार्दपूर्ण माध्यम बने रहना आवश्यक है, क्योंकि राज्य के विकास के लिए विवेकपूर्ण नीतियों पर व्यापक सहमति बनाने हेतु नेताओं के बीच सहयोग और सामंजस्य अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से होने वाली कटु और अस्वस्थ बहसें, जो अब एक अंतहीन तमाशे का रूप ले चुकी हैं, नागरिकों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता को कमजोर कर रही हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा को भी कम कर रही हैं। पंजाब जब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब उसे ऐसे नेताओं के नेतृत्व वाली सरकार की आवश्यकता है, जिनमें 'दुस्साहसी आदर्शवादी, हो' ऐसे नेता जो ऐसी दिशा तय कर सकें, जिससे लोगों में आशा का संचार हो और रोजगार सृजन, व्यापक नशे की समस्या से निपटने के लिए सार्थक नीतियों, राज्य की शक्ति के घोर दुरुपयोग और उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन से जुड़े जटिल प्रश्नों पर विचारपूर्ण दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण तथा सांझी विरासत पर आधारित सामाजिक सौहार्द के संरक्षण के माध्यम से उस आशा को ठोस रूप दिया जा सके।

दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में कैसे मात खा गई कांग्रेस

सचिन शर्मा

पिछले कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने दो महत्वपूर्ण चुनाव गंवा दिए। राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से भाजपा से पटखनी खा गई वहीं दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों में 11 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई (ह्स्ड्ढ) को चारों में से कोई भी सीट नहीं मिली। ठीक इन चुनावों के पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीत का बढ़िया मौका माना जा रहा था। कारण वही थे। यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में सामान्य जाति के लोगों ने सवर्ण मोर्चे बना लिए थे। इसके बाद शुरू हुई बहस ने आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट को भी साथ ले लिया था। राजस्थान में खासा प्रभाव रखने वाली करणी सेना भाजपा के इन फैसलों के खिलाफ खुलकर सामने आ रही थी उसके बाद भी कांग्रेस ने राजस्थान के निकाय चुनाव गंवा दिए। वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े आंदोलन के बाद कांग्रेस ने भी %ल्ट्ठ्´% को साथ लाने की भरपूर कोशिश की। राहुल गांधी लगातार अपने कार्यक्रम %छात्रों की गूंज% को कई बड़े शहरों में ले जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं। उनके प्रमुख मुद्दों पर बहस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बावजूद कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई को दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों इस दशक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंतिम समय तक आगे दिख रही कांग्रेस फिर से अंतिम रह गई।

दिल्ली विवि छात्रसंघ (छ्रस्) चुनाव में कांग्रेस ने उदाहरण पेश किया है कि आंतरिक गुटबाजी किस प्रकार घातक हो सकती है। कांग्रेस आंतरिक कलह और गुटबाजी के लिए जानी भी जाती है। राजस्थान के निकाय चुनावों में भी उसपर आंतरिक गुटबाजी भारी पड़ी है। वही काम कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के विराट और सफल आंदोलन के बाद जब भाजपा बैकफुट पर दिख रही थी और यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किए जाने पर घेरे जाने से भी परेशान थी उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई। पिछले सप्ताह जब डूसू चुनावों के नतीजे आए तो एनएसयूआई का सूपड़ा साफ था। पिछले 11 साल में ऐसा पहला मौका था जब एनएसयूआई चारों प्रमुख पदों में से एक पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार केन्द्रीय पदों में से तीन पर जीत दर्ज कर ली। उसके यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए लेकिन उपाध्यक्ष एक निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन चुने गए। यह शौकीन ही एनएसयूआई के लिए विनाशक साबित हुए। यही उम्मीदवार पहले एनएसयूआई की तरफ से उपाध्यक्ष पद के दावेदार थे। इन्हें टिकट दिया भी गया था लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया। इनके स्थान पर कांग्रेस के एक बड़े नेता मनीष चतरथ के बेटे वीर चतरथ को टिकट दे दिया गया। मनीष कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं। उनका प्रभाव अपने बेटे को टिकट दिलाने के काम तो आया लेकिन उसे जिताने के जरा भी काम नहीं आया। इतना ही नहीं छात्रों के बीच अपनी जबरदस्त पकड़ की वजह से दीपांशु शौकीन ने अपनी जीत तो पक्की की ही साथ ही एनएसयूआई के बाकी उम्मीदवारों की हार भी सुनिश्चित कर दी। दीपांशु ने इन चारों उम्मीदवारों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने पिछले तीस साल के डूसू चुनावों में किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिले वोटों से कहीं अधिक वोट हासिल किए। उन्हें 30,615 वोट मिले और उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार ईशु मौर्या को सबसे बड़े अंतर 13,705 वोट से हराया। वीर चतरथ का हाल तो ऐसा हो गया कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले।

विनोद जाखड़ वर्तमान में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने डूसू अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा की सिफारिश की थी। जाखड़ भविष्य में राजस्थान से विधायक के लिए टिकट का सपना देख रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के मीणा मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसा किया लेकिन वो भविष्य के चक्कर में वर्तमान को भूल गए। उनका यह निर्णय बेहद खराब साबित हुआ। जाखड़ के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से एनएसयूआई का काम देख रहे हैं। वो इस छात्र ईकाई के मुख्य मार्गदर्शक और प्रभारी है। शौकीन का टिकट काटने का काम कन्हैया कुमार ने किया। अंदरखाने बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार और दीपांशु शौकीन के बीच %ईगो इशु% आ गया था। हालांकि दोनों ही छात्र नेताओं की पृष्ठभूमि एक मायने में समान ही है। शौकीन पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी गांव के एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं जबकि मां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। वहीं कन्हैया कुमार की मां भी बेगूसराय (बिहार) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ऐसे में इन दोनों ही छात्र नेताओं को जहां मिलकर काम करना था वहां अहंकार ने काम बिगाड़ दिया। शौकीन के समर्थन में आगे आए छात्रों ने इस बात का खूब प्रचार किया कि एनएसयूआई और कांग्रेस में साधारण परिवार से आने वाले छात्रों का कोई सम्मान नहीं है और वो पार्टी भाई-भतीजावाद में ही लगी हुई है इसलिए वीर चरतथ को टिकट दिया गया। शौकीन छात्रों के बीच पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर उभरे। दिल्ली विवि के साउथ कैंपस के पास ढही पांच मंजिला इमारत सत्य निकेतन में लगभग आधा दर्जन छात्र मारे गए थे। उन छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिलवाने और अन्य मांगों के साथ शौकीन ने यह चुनाव नंगे पैर घूमकर लड़े। इसका खूब प्रचार किया गया। शौकीन का यह कैंपेन एनएसयूआई के बाकी कैंडिडेट्स पर भी भारी पड़ गया। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब पिछले माह आए पंजाब विवि के छात्रसंघ चुनाव नतीजों में भी एबीवीपी ने बाजी मार ली थी। वो चुनाव भी कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में ही लड़े गए थे। पूरे देश में घूम-घूम कर राहुल गांधी जहां एक ओर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को चला रहे हैं वहीं दूसरी ओर उसके नतीजे में एनएसयूआई एक के बाद एक चुनाव हार रही है। इस बात से उखड़कर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार की 15 मिनट तक जमकर क्लास भी ली लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुगकर उड़ चुकी थी।

हाल ही में घोषित हुए राजस्थान नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस शुरू में कई वजहों से आगे दिख रही थी। सामान्य वर्ग का भाजपा की केन्द्र सरकार से रोष उसके लिए सबसे बड़ा ईंधन था। करणी सेना राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी। वोटरों को लामबंद कर रही थी। राजस्थान में सामान्य वर्ग के वोटरों का हिस्सा 20 से 25 प्रतिशत के बीच है। ऐसे में भाजपा को डर सता रहा था कि कहीं अगड़ी जातियां इस चुनाव में उसके खिलाफ लामबंद हो गईं तो इन चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। जब नतीजा आया तो मात्र एक (0 ।94) प्रतिशत वोट भाजपा के खाते में कांग्रेस से अधिक गया था लेकिन इस जरा से अंतर से ही कांग्रेस चित हो चुकी थी। 301 घोषित निकाय प्रमुखों के नतीजों में से भाजपा ने 198 पर जीत दर्ज कर ली थी जबकि कांग्रेस मात्र 94 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस झटके के बाद तो जैसे कांग्रेस को कई झटके लगे। 7 नगर निगमों (मेयर चुनाव) में से भी भाजपा ने 6 पर कब्जा जमा लिया जबकि कांग्रेस के हिस्से सिर्फ एक निगम बीकानेर आया। कुल मिलाकर भाजपा ने शहरी निकायों के 10,245 वार्डों के इन चुनावों में 4,179 वार्डों में जीत हासिल की जबकि कांग्रेस 3,613 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर में अपने मेयर बनाए जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ बीकानेर आया।

राजस्थान स्थानीय चुनाव में भाजपा की जीत तो ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बाद भी वह सत्ता में आने लायक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस बात को सिर्फ निर्दलीयों के प्रदर्शन से समझा जा सकता है। इस चुनाव में रिकार्ड 2273 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यही नहीं 7 निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष बन गए। सफल हुए निर्दलीयों में उन बागियों की संख्या बहुत ज्यादा थी जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। इस बात से उत्साहित प्रदेश की भाजपा सरकार ने चुनाव बाद पार्षदों की खूब तोड़फोड़ की और अपने अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़तोड़ किया। इसके अलावा इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को अच्छा खासा कांटा चुभोया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में आधा (0 ।47) प्रतिशत वोट हासिल कर लिया। इतना ही नहीं उसने 42 वार्ड भी जीत लिए। बारां में उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया जहां नगर परिषद में उसने 60 में से 31 वार्ड जीत लिए और निकाय प्रमुख का पद भी जीत लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काटा हो।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

7- बौद्धों के तथा कथित दार्शनिक सम्प्रदाय

गतांक से आगे...

योगाचार ज्ञानवादी है, जिसका सिद्धान्त बहुत अंश तक पाश्चात्य दार्शनिक बार्कले के सिद्धान्त के समान है। जहाँ तक इस सम्प्रदाय का प्रश्न है, सर्वदर्शनसंग्रह का वर्णन लगभग ठीक ही है। योगाचार के दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण आगे किया जायगा। चौथा दार्शनिक सम्प्रदाय माध्यमिक या शून्यवादी है। इसका निरूपण भी, गम्भीर तत्त्व दृष्टि में जाने की बात छोड़कर, ऊपरी तौर पर सर्वदर्शनसंग्रह में ठीक ही किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय दर्शन की पिछली शताब्दियों में अर्थात् 14 वीं शताब्दी के कुछ पहले से वाद के समय तक वेदान्त के सिद्धान्तों के अध्ययन के साथ साथ योगाचार और माध्यमिक के सिद्धान्तों को बहुत अंश तक वैदिक दर्शनों का अध्ययन करने वाले समझते थे परन्तु वैभाषिक और सौत्रान्तिक दार्शनिक सम्प्रदायों के विषय में उनको उतनी जानकारी नहीं थी। इसलिये उपर्युक्त दोनों दार्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का सर्वदर्शन-संग्रह में किया हुआ निरूपण, जैसा कि ऊपर कहा गया, बहुत अंश तक भ्रमपूर्ण है। परन्तु सर्वदर्शनसंग्रह के बौद्ध दर्शन के निरूपण में जो मौलिक दोष है वह यह है कि सारे बौद्ध दर्शन का चार सम्प्रदायों में विभाजन किया गया है, जिसके लिये कोई बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों का आधार प्रतीत नहीं होता। वर्तमान लेखक का जहां तक बौद्ध दर्शन के मूलग्रन्थों या तत्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन है, उसमें कहीं भी बौद्ध दर्शन को निश्चित रूप से इन चार सम्प्रदायों में बांटा गया हो, ऐसा नहीं मिलता। यह ठीक है कि बौद्ध दर्शन के अन्तर्गत ये चार सम्प्रदाय थे, परन्तु केवल ये चार ही विशेष रूप से बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय हों और उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का उस प्रकार का पारस्परिक तारतम्य हो, जैसा सर्वदर्शनसंग्रह में दिया गया है, यह बात कम से कम बौद्ध दार्शनिक साहित्य पर आश्रित प्रतीत नहीं होती।

क्रमशः ...

पं. दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. राकेश मिश्र

25 सितंबर 1916 को फरह (मथुरा) में जन्मे पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ को सुदृढ़ करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्घोष किया। ऐसे महामानव श्रद्धेय पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम सभी सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण हो आता है, जिनका व्यक्तित्व विराट और संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। दूरदर्शी सोच, समदर्शी सिद्धांत, उत्कृष्ट चिंतन और राष्ट्र के लिए त्याग का ही दूसरा नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय है। भारत की धरती पर महामानव के रूप में अवतरित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी व सच्चे राष्ट्र भक्त के रूप में भारतवासियों के प्रेरणास्त्रोत रहे हैं और रहेंगे। राष्ट्र की सेवा में सतत समर्पित दीनदयालजी भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में शिखर पर देखना चाहते थे। वे एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा के सूत्रधार थे, जिसमें राजनीति और सरकार, सेवा का साधन हो। राजनीति में कथनी और करनी में अंतर न रखने वाले इस महामानव ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था बनाए रखी। व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में भी सिद्धान्त और व्यवहार में समानता रखने वाले इस महान व्यक्तित्व को भी काफी विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन, राष्ट्रभक्ति जिनका ध्येय हो, समाज का कल्याण जिनका चिंतन हो और ईमानदारी जिसका चरित्र हो, उसे कोई भी ताकत उसके उद्देश्यों से डिगा नहीं सकता है। आज सुखद अनुभूति हो रही है कि उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी साकार कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति के महामानव अजातशत्रु पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया। भारतीय जनसंघ के निर्माता पं. दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्वदृष्टि प्रदान करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने देश को एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा दी। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। एकात्म मानववाद की अवधारणा पर आधारित राजनीतिक दर्शन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनके अनुसार एकात्म मानववाद मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकीकृत कार्यक्रम है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी आंदोलन हुए उसका एकमात्र ध्येय था स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेकिन, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी दिशा क्या होगी? हम किस मार्ग से अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकेंगे? कौन सा ऐसा विचार होगा जो हमारे समेकित उन्नयन में सहायक होगा? किस सिद्धांत का निरूपण कर हम व्यष्टि से समष्टि के रूप में अपनी खोई गरिमा प्राप्त कर सकेंगे? क्या होगा वह दर्शन जिसके माध्यम से हम अपनी अधुनातन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित हों एवं साथ ही अपनी महान संस्कृति को भी अक्षुण्ण रख सकें? इसका विचार नहीं किया गया।

अंतहीन युद्धों का रंगमंच : तीन महाद्वीपों के दिलचस्प त्रिकोण!

शंकर अय्यर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डायरी अपने आप में एक युद्ध का मैदान है। अमेरिकी दूतों के मॉस्को से युद्धविराम की योजना लेकर लौटने के तुरंत बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर एक घंटे बातचीत की। लेकिन, युद्धविराम सिर्फ सप्ताहांत तक ही टिक सका और सोमवार को फिर लड़ाई शुरू हो गई। ट्रंप के सामने कई अहम काम हैं-उनके 'बड़े बॉलरूम' पर चर्चा, मीडिया पर रोक, कैनेडी सेंटर को गिराना, ताइवान और वेनेजुएला के तेल से जुड़े मुद्दे और एआई को लेकर बढ़ते डर को खत्म करना। इसके साथ ही मध्यावधि चुनावों की रैलियों में अपनी छवि संभालने की चुनौती भी है।

ट्रंप की डायरी के अनुसार, वाशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे ?हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं की है, लेकिन माना जाता है कि ओवल ऑफिस में भारत को लेकर चर्चा होती रहती है। तीन महाद्वीपों के तीन नेताओं के इस दिलचस्प त्रिकोण में, ट्रंप युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं-एक वह युद्ध, जिसे उन्होंने एक दिन में खत्म करने का वादा किया था और दूसरा वह नया युद्ध, जिसे शुरू न करने का वादा किया था। पिछले शुक्रवार तक उनकी डायरी में एक और एंट्री जुड़ गई-एचआर 5334, 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026'। यह विधेयक अमेरिकी संसद से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। इसमें 200 से अधिक धाराएं हैं, जिनमें कड़े दंड के प्रावधानों के साथ कुछ दिलचस्प छूट भी दी गई है। इसकी धारा 114 की खास बात यह है कि यह अमेरिका में कम-संवर्धित यूरेनियम के आयात पर लागू नहीं होगी।

ग्राहम कानून रूस पर प्रतिबंध लगाता है और ईरान पर लगे प्रतिबंधों की अवधि को पांच साल और बढ़ाता है। साथ ही, यह रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, जिनमें भारत भी शामिल है। चीन वह दूसरा देश है, जो आमतौर पर ज्यादा तेल खरीदता है। अगर इसे रूस के खिलाफ एक कानून के रूप में देखें, तो यह सीधा और कड़ा हथियार है। पर, यदि इसे तीन देशों के बीच समीकरण के तौर पर देखा जाए, तो यह शांति का संभावित हथियार भी बन सकता है। पहली नजर में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को एक ऐसा आर्थिक हथियार दिया है, जिसका मकसद दबाव डालकर कुछ हासिल करना है। सवाल यह है कि क्या टैरिफ की धमकी से रूस या चीन को झुकाया जा सकता है। अब तक का अनुभव कुछ खास उत्साहजनक नहीं रहा है।

रूस से भारत के तेल आयात पर ग्राहम कानून के संभावित असर को लेकर काफी चर्चा है। भारत ने तेल कंपनियों के जरिये झटके को सहकर और करों में बदलाव करके कीमतों को काफी हद तक स्थिर रखा है। हालांकि, कीमतों का दबाव रिफाइनरियों व सरकारी राजस्व पर पड़ रहा है। इसका असर करदाताओं और महंगाई के आंकड़ों पर भी पड़ेगा। अब तक भारत ने प्रतिबंधों से बचते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी है और अपनी अर्थव्यवस्था के हित में वेनेजुएला से लेकर ईरान तथा रूस तक हाइड्रोकार्बन के वैकल्पिक स्रोत तलाशे हैं। पर क्या अमेरिका चीन को रूस व ईरान से तेल या गैस खरीदना बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है?

ग्राहम कानून के तहत कार्रवाई की बात करें, तो बीजिंग, दिल्ली की तुलना में कहीं ज्यादा आगे है। कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति को इसके लागू होने के 30 दिनों के भीतर टैक्स लगाना होगा। सैद्धांतिक रूप में बहुत कुछ संभव है, पर हकीकत में संभावनाओं का दायरा काफी बड़ा है। मसलन, कहा जा सकता है कि चीन के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का अमेरिकी कर्ज है और वह रेयर अर्थ से लेकर दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक की उत्पादन श्रृंखला रोक सकता है। चीन के पास ये विकल्प जरूर हैं, लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि चीन को इनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

धमकी, दबाव वाली कूटनीति और सजा की कार्रवाई, हालात और उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करती हैं। इसमें एक आर्थिक पहलू है और दूसरा भू-राजनीतिक ढांचा। आर्थिक हालात के आंकड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा आर्थिक संकेत राजनीतिक भी है। अमेरिका में गैसोलीन की औसत कीमत 4.2 डॉलर प्रति गैलन से ज्यादा और डीजल की 6.2 डॉलर से अधिक है। मध्यावधि चुनाव से पहले हुए एक सर्वे में 84 प्रतिशत डेमोक्रेट, 73 प्रतिशत निर्दलीय और 66 प्रतिशत रिपब्लिकन इससे सहमत थे कि टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ी हैं। कैटो फॉल 2026 के सर्वे में 75 प्रतिशत लोगों ने माना कि टैरिफ का असर पड़ेगा। कीमतें मांग और आपूर्ति से तय होती हैं। इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड करीब 110 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, क्योंकि हूतियों के पाइपलाइन पर हमलों के बाद सऊदी अरब को उत्पादन घटाना पड़ा और यूरोप के लिए कुछ शिपमेंट रद्द करनी पड़ी। आपूर्ति घटने का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है।

भारत का कहना है कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। भारत यूरोप को डीजल आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में, किसी भी दबाव या धमकी से उत्पादन घटेगा और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी होगी। खासकर नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद बने भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए लगता है कि अमेरिका डेंग शियाओपिंग का तरीका अपनाते हुए सावधानी से कदम उठाएगा। शी और ट्रंप की बैठक के एजेंडे में बुसान और बीजिंग में बनी सहमति को आगे बढ़ाने की बात है-जिसमें व्यापार युद्धविराम, रेयर अर्थ, ताइवान और एआई जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन, एजेंडे में शामिल बातों से ज्यादा अहम वे मुद्दे हैं, जो इसमें नहीं हैं। अमेरिका ईरान और यूक्रेन में चल रहे युद्धों को खत्म करने का रास्ता तलाशना चाहेगा। किसी भी बड़ी कामयाबी का रास्ता ग्राहम कानून के तहत छूट देने के राष्ट्रपति के अधिकार से ही बनेगा। चीन के पास ईरान और रूस पर असर डालने की ताकत है-चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक।

इनमें से कोई भी चीज अचानक नहीं हो रही है। जिस दिन सदन में ग्राहम कानून पर मतदान हुआ, उसी दिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाकर 3.75 से चार प्रतिशत कर दी। अगस्त में अमेरिका का कर्ज 40 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया और यह हर दिन करीब 7.35 अरब डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। महंगाई के राजनीतिक जोखिम से जूझ रही अमेरिकी सरकार वैश्विक तेल कारोबार पर दबाव डालकर बच नहीं सकती। उसे इस कानून की कीमत दो बार चुकानी पड़ेगी-एक बार पेट्रोल पंप पर और दूसरी बार मतदान में।

आज का इतिहास

1237 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कॉमन बॉर्डर को लेकर संधि हुई थी।
1340 फ्रांस और इंग्लैंड ने निशस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
1524 वास्कोडिगामा आखिरी बार वायसराय बनकर में भारत आया था।
1639 अमेरिका में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी।
1654 इंग्लैंड और डेनमार्क ने व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
1846 अमेरिकी सेना ने मेक्सिको के मोंटेरी पर कब्जा किया था।
1897 ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरूआत हुई थी।
1911 फ्रांसीसी युद्धपोत लिब्रीटे में टूलॉन हार्बर पर विस्फोट से 285 लोगों की मौत।
1914 भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल का जन्म हुआ।
1916 अर्थशास्त्री और महान चिंतक पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था।
1955 रॉयल जॉर्डन वायु सेना की स्थापना हुई थी।
1974 पांचवी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई।
1974 अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
1981 मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था।
1984 मिस्र और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए।
1985 अकाली दल ने पंजाब के चुनाव में जीत दर्ज की।
1992 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ऑब्जर्वर ने स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा था।
1996 तालिबान के लड़ाके काबुल के बेहद करीब पहुंचे थे।
1999 आठवें सैफ खेलों का उद्घाटन काठमांडू में हुआ था।
2001 सऊदी अरब ने तालिबान मिलिशिया से संबंध तोड़ा था।
2003 गयूम ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव छठी बार जीता था।
2006 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार सिंध के थारपाकर ज़िले के हिन्दू युवक दानेश को पाक सेना में शामिल किया गया था।
2006 अंतरिक्ष की सैर पर निकली ईरान की पहली महिला अनुशेह अंसारी।
2007 शेर बहादुर देउबा के नेतृ?व वाली डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था।
2008 चीन ने अंतरिक्ष यान शेंझो-7 का प्रक्षेपण किया था।
2009 भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग पाँच हज़ार करोड़ रुपये के हवाला नेटवर्क का भण्डाफोड़ किया था।
2011 नेपाल में निजी एयलाइन के विमान की दुर्घटना में सभी 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
2015 सिंगापुर में प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा था।

क्या सच में मनमर्जी करते हुए ज्ञानेश कुमार ने सरकार की शक्तियों को भी ठेंगा दिखा दिया?

अभिनय आकाश

क्या चुनाव आयोग के अंदर किसी की मनमर्जी चल रही है? आखिर क्या सच में दो चुनाव आयुक्तों ने नियम पालन न होने की शिकायत दर्ज कराई थी? क्या नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया में कोई अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई। फॉर्म-6 की शक्तियों के मामले में सरकार की शक्तियों को भी ठेंगा दिखा दिया गया? चुनाव आयोग के जिन अधिकारियों को वोटर जोड़ने और हटाने का हक है, उनके हाथ क्या किसी ने बांध दिए? देशभर के वोटरों के डेटा को दिल्ली से कंट्रोल करने का चलन क्या शुरू किया गया? महीनों में 14 बार और एक ही दिन में कम से कम चार बार दो चुनाव आयुक्तिों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करानी पड़ी। इन आपत्तियों के बावजूद फैसले क्यों ले लिए गए। क्या सच में ऐसी परिस्थितियां बनी की चुनाव आयुक्तों को जाकर कैबिनेट सेक्रेटरी से शिकायत करनी पड़ गई।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के भीतर कामकाज और पारदर्शिता को लेकर बड़ा अंदरूनी विवाद सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में बिना उनकी जानकारी के लिए गए कई बड़े फैसलों और जारी किए गए आदेशों पर कड़ा ऐतराज जताया है।

अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दर्ज की गई लिखित आपत्तियों की समीक्षा की गई है। इस दौरान दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराते हुए सवाल किया कि आखिर उनकी सहमति और जानकारी के बिना ये आदेश और निर्णय कैसे जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दो आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां मतदाता सूची और पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित थीं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं-

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी कार्यप्रणाली और उस पर लिए गए फैसले।

फॉर्म-6 में बदलाव: नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में किए गए संशोधन।

मतदाताओं के नाम जोड़ना और हटाना: वोटर लिस्ट में नए नामों को शामिल करने और पुराने नामों को हटाने की प्रक्रिया।

डेटा तक पहुंच: मतदाता सूची के संवेदनशील डेटाबेस का रखरखाव और उसकी एक्सेस।

अपील प्रक्रिया: मतदाता सूची से जुड़े निर्णयों के खिलाफ दायर होने वाली अपीलों की सुनवाई और निपटारे की व्यवस्था।

चुनाव आयोग का जवाब- चुनाव आयोग के सूत्रों ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद हैं। सूत्रों ने कहा कि एसआईआर से जुड़े फैसलों समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए थे। सूत्रों ने कहा भारत के चुनाव आयोग के सभी फैसले, जिनमें एसआईआर भी शामिल है, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं। ईसीआई सूत्रों ने कहा कि हालांकि किसी भी मामले पर दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के सभी फैसले जिनमें एसआईआर भी शामिल है। सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में फैसलों को लेकर सामने आई अंदरूनी आपत्तियों की खबरों के बीच अब आयोग से

जुड़े सूत्रों का स्पष्टीकरण सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मसलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी टिप्पणियां और सवाल जरूर रखे थे, जिन पर अंतिम फैसला लेने से पहले विचार भी किया गया था। हालांकि, किसी भी चुनाव आयुक्त ने अंतिम फैसले के खिलाफ कोई औपचारिक %डिसेंट% (असहमति नोट) दर्ज नहीं कराया। आयोग का कहना है कि जिन फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सभी आदेशों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

क्या होता है ऑब्जर्वेशन और डिसेंट में फर्क?

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि किसी भी नीतिगत मामले पर आंतरिक चर्चा के दौरान आयुक्तों द्वारा सवाल उठाना या टिप्पणियां (ऑब्जर्वेशन) करना एक सामान्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

ऑब्जर्वेशन (टिप्पणी/राय): चर्चा के दौरान किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगना या सुझाव देना।

डिसेंट (औपचारिक असहमति): जब कोई आयुक्त बहुमत के अंतिम फैसले से पूरी तरह असहमत हो और आधिकारिक रिकॉर्ड पर अपनी असहमति दर्ज कराए।

तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका व अधिकार बराबर होते हैं। यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।

यह स्पष्टीकरण उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई थी और कई कदम बिना उनकी जानकारी के उठाए जाने पर सवाल खड़े किए थे।

चुनाव आयोग के कामकाज में आयुक्तों के बीच मतभेद या अलग राय दर्ज कराने का यह पहला मामला नहीं है। भारतीय चुनावी इतिहास में ऐसे कई अहम मौके आए हैं-

2019 का अशोक लवासा मामला: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों (जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण भी शामिल थे) के निपटारे पर अपने साथी आयुक्तों से अलग राय दर्ज कराई थी।

2009 का गोपालस्वामी विवाद: वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने सोनिया गांधी से जुड़े एक मामले में चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और नवीन चावला के रुख से अलग औपचारिक राय रखी थी।

वर्तमान में चुनाव आयोग तीन सदस्यीय निकाय के तौर पर काम करता है, लेकिन व्यवस्था हमेशा ऐसी नहीं थी। 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तब यह केवल मुख्य चुनाव आयुक्त वाला एक सदस्यीय निकाय था। 1950 से लेकर 1989 तक आयोग इसी एकल व्यवस्था के तहत संचालित होता रहा। बाद में इसे बहु-सदस्यीय बनाया गया, ताकि सभी महत्वपूर्ण चुनावी फैसलों में सामूहिक चर्चा और आम सहमति सुनिश्चित की जा सके।

इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है; विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और सीईसी ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग की है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। पार्टी ने कहा कि शिकायतों से साफ़ है कि तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ़ ज्ञानेश कुमार की ही चलती है। कांग्रेस ने कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग में वोट चोरी और राजनीतिक दखलंदाज़ी के अपने पुराने आरोपों को दोहराया। पार्टी ने कहा ज्ञानेश अपने बॉस मोदी की तरह ही तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और मोदी को खुश करने के लिए वोट चोरी में लगे हैं। हमने पहले भी कहा है - मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्ज़ा कर लिया है। ज्ञानेश कुमार मोदी की कठपुतली हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट इस बात को साबित करती है। मोदी और ज्ञानेश ने मिलकर देश के लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन याद रखें - जब समय आएगा, तो सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा, ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। इस अपराध के लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट को बेहद गंभीर बताया और आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त अपनी सही ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के सदस्य फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद नहीं हैं या उनकी चिंताओं को नहीं सुना जाता है, तो इसके लोकतंत्र पर गंभीर असर पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, इसका सीधा मतलब है कि सभी चुनाव आयुक्त अपनी सही ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे हैं। अगर किसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को सही काम करने की आज़ादी नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं। सत्ता में बैठे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर लोकतंत्र के साथ धोखा करना एक गंभीर संवैधानिक अपराध है। यह लोकतंत्र को खत्म करने की साज़िश से कम नहीं है।

राजनीति को सतही बना देता है मसखरापन

विश्वनाथ सचदेव

राजनीति की दुनिया की एक विवशता या विशेषता यह है कि उसमें किसी को अपना कहाङ्किया कभी गलत नहीं लगता, और यदि यही सब विरोधी करे तो वह कभी सही नहीं माना जाता। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में इंदौर में दिखा जब लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा चलाए जा रहे अभियान 'छात्रों की गूंज' में एक मसखरे को मंच पर बुलाना जरूरी समझा गया। मसखरा शब्द में कुछ हल्कापन सुनाई देता है, शायद इसीलिए आज की पीढ़ी इसे अंग्रेजी में 'स्टैंड-अप कामेडियन' कहना पसंद करती है। नेता विपक्ष के उस कार्यक्रम में पता नहीं क्या सोचकर एक कामेडियन को सम्मिलित करना जरूरी समझा गया था, पर जो हुआ उसे देखकर अच्छा नहीं लगा। राजनेताओं की मिमिक्री अथवा नकल उतारना एक स्वाभाविक-सी बात मानी जाती है। इस मिमिक्री को देखने-सुनने वाले अक्सर इस पर हंस लेते हैं, और बात वहीं समाप्त हो जाती है। यह सही है कि राजनीति में मिमिक्री का उपयोग सिर्फ हंसने-हंसाने के लिए नहीं होता। उद्देश्य अपने विरोधी को नीचा दिखाना ही होता है, इसलिए जिसका मजाक उड़ाया जाता है, वह और उसके समर्थक उसे सही नहीं मानते और मजाक उड़ाने वालों को वह कभी गलत नहीं लगता।

होना तो यह चाहिए था कि मिमिक्री के इस प्रकरण को भुला दिया जाता, पर मामला राजनीतिक नफे-नुकसान का है, इसलिए बात बढ़ गई है। भाजपा वालों को यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष ने यह 'घटिया' चाल चली है, और कांग्रेस के समर्थक इसे अपना 'मास्टर स्ट्रोक' मान रहे हैं।

हकीकत यह भी है कि दोनों पक्षों में एक होड़-सी लगी है एक-दूसरे को नीचा दिखाने की। राजनीति की दृष्टि से इस मिमिक्री-प्रकरण का भले ही कुछ भी अर्थ हो, पर इसका एक सीधा-सा अर्थ यह भी है कि मिमिक्री ने हमारी राजनीति को एक घटियापन से जोड़ दिया है।

वैसे भी राजनीति को 'शैतानों की अंतिम शरणस्थली' कहा गया है, पर राजनीतिक विरोधियों पर इस तरह के घटिया प्रहार हमारी राजनीति के ओछेपन को ही उजागर करते हैं। एक-दूसरे का मजाक उड़ाना हमेशा गलत नहीं होता, पर जिस तरह के वार-प्रतिवार हमारी राजनीति में दिखने लगे हैं,

उनके घटियापन को किसी भी तरह के बचाव से छिपाया नहीं जा सकता। इस संदर्भ में हमारे छुटभैया राजनेताओं से लेकर बड़े से बड़े राजनेता का दामन भी मैला दिखाई देता है। इंदौर के 'छात्रों की गूंज' के कार्यक्रम में मसखरे को मंच पर बुलाकर इस मैलेपन को ही उजागर किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर उठते सवाल

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

अमेरिका-ईरान युद्ध हो या फिर रुस यूक्रेन युद्ध और इसी तरह दुनिया के देशों के सामने आ रही गंभीर समस्याओं के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते आज दुनिया के देश ईंधन की समस्या से दो चार हो रहे हैं। शक्तिशाली देशों के दादागिरी चरम पर पहुंचती जा रही है। आज हार्मुज का रास्ता बंद है तो अन्य वैकल्पिक रास्तों पर भी अवरोध आ रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों की समस्याओं के प्रति कोई गंभीर नहीं है। पेट्रोल पदार्थों और एलपीजी की आवाजाही प्रभावित होने से ईंधन के भावों में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा संकट हो रहा है। आवागमन के साधनों का प्रमुख माध्यम पेट्रोल-डीजल आदि है और उनकी उपलब्धता पर पड़ रहे असर के कारण सभी देशों में सीधे आमजन प्रभावित हो रहे हैं। आखिर ऐसे समय में ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पर जो तस्वीर सामने आ रही हैं वह साफ है कि युद्ध करने वाले देशों पर दबाव ड़ालने की स्थिति में ना तो कोई वैश्विक संस्था रह गई है और ना ही कोई सर्वमान्य वैश्विक नेता। आखिर यह कोई एक दिन का पराभव तो नहीं हैं बल्कि देखा जाएं तो संयुक्त राष्ट्र को तो योजनाबद्ध तरीके से शक्तिहीन किया गया है। अमेरिका जैसे देशों द्वारा बिना बजह फण्डिंग बाधित या कम की जाती है तो वीटो पॉवर स्वयं में नकारात्मक भूमिका में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों के प्रवेश को टाला जा रहा है तो इसे पंगु बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने सकारात्मक भूमिका निभाई। देशों के बीच परस्पर सहयोग व समन्वय का परिणाम यह रहा कि दुनिया के देश कोविड वैश्विक संकट से मुकाबला करने में सफल रहे। खैर पर दुनिया के देशों के बीच युद्ध, युद्ध के हालात और तनाव की स्थिति को कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह विफल रहा है। इस विफलता के कारणों का अलग से विश्लेषण किया जा सकता है। पर एक बात साफ है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर समग्र रुप से देखा जाएं तो भरोसा 57 प्रतिशत ही रह गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति नकारात्मक विचार रखने वालों का प्रतिशत 37 प्रतिशत ही है। भरोसे के यह आंकड़ें अगस्त 26 के ही हैं और यह प्यू रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में सामने आये हैं। दुनिया के देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ पर सबसे कम भरोसा करने वाला देश इजरायल है। इजरायल के 79 प्रतिशत लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पर भरोसा नहीं रखते। इजरायल ही क्या जापान, तुर्की, पाकिस्तान, ग्रीस, फिलिस्तीनी क्षेत्र के देश आदि ऐसे देष है जो यूएन पर भरोसे के मामले में लकारात्मक सोच रखते हैं। हांलाकि कनाड़ा, अमेरिका, नाइजीरिया, अधिकांश योरोपीय देश, घाना, केन्या व अधिकांश एशिया प्रशांत के देशों का भरोसा अधिक है। यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सोच सकारात्मक रखते हैं। नाइजीरिया, फ्रांस यहां तक कि अमेरिका आदि में संयुक्त राष्ट्र के प्रति सकारात्मकता में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के देशों में एकमात्र श्रीलका ऐसा देश है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भरोसे में बढ़ोतरी देखी गई है।

सौ टके का सवाल यह है कि आज यूएन दुनिया के देशों के बीच संघर्ष या तनाव कम करने में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। अमेरिका-ईरान या रुस-यूक्रेन युद्ध सबके सामने है। यह कोई दो देशों के बीच युद्ध नहीं है अपितु इन युद्धों की आंच दुनिया के अधिकांश देशों पर किसी ना किसी रुप में पहुंच रही है। आज वर्चस्व सिद्ध करने या दादागिरी ही एक मात्र ध्येय रह गया है। पर रुस और अमेरिका अभी भी यह नहीं समझ पा रहे कि युद्धारंभ से पहले चंद घंटों या चंद दिनों का युद्ध समझ कर जोश में आ गए थे आज हालात उनके लिए ना निगलते बन रही हैं और ना ही निगलते बन रही है। इन युद्धों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि सामने वाला देश कितना भी छोटा क्यों ना हो पर युद्ध को लंबा किसनी की क्षमता उसमें हैं। अमेरिका इजरायल ने जब ईरान पर आक्रमण किया तब उन्होंने बहुत गाल बजाएं थे पर आज जो हालात है वह सबके सामने हैं। यही रुस यूक्रेन की बात है चंद दिनों का युद्ध कब सालों लंबा युद्ध होता जा रहा है यह सबके सामने हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी या कारगर होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। आज संयुक्त राष्ट्र संघ नख-दंत विहीन संस्था रह गया है।

अमेरिका सहित विकसित देश फण्डिंग में कमी कर देते हैं या रोक देते हें तो यूएन अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि देशों पर दबाव बना सके। सुरक्षा परिषद का वीटो का अधिकार भी एक प्रमुख बाधा ही है। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश को लंबे समय से रोका जा रहा है। नए सदस्य किसी को स्वीकार ही नहीं हो रहे।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन एक सकारात्मक संदेश के साथ हुआ था। समय आ गया है जब दुनिया के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नए सीरे से तय करनी होगी। यूएन को दिखावटी संस्था के स्थान पर अधिकारपूर्ण और निर्णय क्षमता युक्त संस्था बनानी होगी। लोगों में विश्वास बनाना होगा कि यूएन केवल संस्था नहीं अपितु वह अपने दायित्वों को पूरा करने और दादागिरी करने वाले देशों पर लगाम लगाने की स्थिति में हो या ना हो पर एक ऐसा भ्रम तो पैदा करने की स्थिति में हो ताकि शक्तिशाली देशों की मोनोपोली को सीमित किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्किये का कश्मीर पर दखल की कोशिश

नीरज कुमार दुबे

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़कर भारत के आंतरिक और द्विपक्षीय विषय में दखल देने की कोशिश की है। एर्दोगन ने कहा कि दक्षिण एशिया में कश्मीर सहित सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हो चुका है।

लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर पर नसीहत देने वाले एर्दोगन क्या पहले अपने पड़ोस में शांति और सीमा विवादों का समाधान करेंगे? उल्लेखनीय है कि तुर्किये के अपने पड़ोसियों के साथ कई पुराने और गंभीर क्षेत्रीय विवाद हैं। यूनान के साथ एजियन सागर और पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्री सीमाओं, महाद्वीपीय पट्टी और विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर लंबे समय से टकराव चला आ रहा है। तुर्किये और साइप्रस के बीच विवाद तो 1974 के बाद से आज तक कायम है और संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था के बावजूद द्वीप विभाजित है। यही नहीं, पूर्वी भूमध्यसागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर भी अंकारा का यूनान और साइप्रस के साथ टकराव रहा है। साथ ही तुर्किये ने उन समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा खोज गतिविधियां की हैं, जिन पर यूनान और साइप्रस अधिकार का दावा करते हैं। इन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में सैन्य तनाव तक पैदा हुआ है।

साइप्रस का सवाल इससे भी ज्यादा संवेदनशील है। तुर्की सेना ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था और आज भी द्वीप का विभाजन कायम है। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर इस विवाद के समाधान की कोशिशें दशकों से चल रही हैं। ऐसे में एर्दोगन अगर दुनिया को सीमा विवादों और संवाद का पाठ पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या वही सिद्धांत तुर्किये अपने पड़ोस में भी उतनी ही गंभीरता से लागू करेगा?

यही वजह है कि एर्दोगन की कश्मीर पर टिप्पणी भारत

के लिए केवल एक बयान नहीं, बल्कि कूटनीतिक दखल के रूप में देखी जा रही है। जबकि भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। साथ ही भारत-पाकिस्तान से जुड़े विषयों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष भी एर्दोगन की ऐसी टिप्पणी पर भारत ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर पर उसका रुख नहीं बदला है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है।

इस बार भी नई दिल्ली ने एर्दोगन की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया है। भारत का संदेश साफ है कि कश्मीर पर बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकती है और आतंकवाद तथा हिंसा के माहौल में संवाद की शर्तें भी भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है।

दूसरी ओर, एर्दोगन की यह सक्रियता तुर्किये और पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी की पृष्ठभूमि में भी देखी जा रही है। अगस्त में तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान अंकारा का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भी भारत-तुर्किये संबंधों में तनाव का बड़ा कारण बना। भारत ने उस दौरान तुर्किये की ओर से पाकिस्तान को मिले समर्थन और सैन्य सहायता पर अपनी चिंता स्पष्ट रूप से दर्ज कराई थी। इसका असर सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्किये की ओर से मिले समर्थन को देखते हुए भारत में तुर्किये के सामान के बहिष्कार की व्यापक मुहिम चली। दिल्ली की आजादपुर मंडी ने तुर्किये से सेब और अन्य फल-सब्जियों के आयात रोक दिये। साथ ही अन्य राज्यों के बाजारों में भी तुर्किये के सेब का बहिष्कार हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में भी कारोबारियों ने तुर्किये के सेब खरीदना बंद कर दिया और स्थानीय तथा दूसरे देशों के विकल्पों की ओर रुख किया। उस समय रिपोर्टों में सिर्फ पुणे के बाजार में ही तुर्किये के सेब के कारोबार का मौसमी मूल्य लगभग 1,000 से 1,200 करोड़ रुपये तक बताया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्किये के मात्र सेब खरीदना बंद कर ही उसे कितना नुकसान पहुँचाया गया था। यही नहीं, व्यापक व्यापार के स्तर पर भी दोनों देशों के बीच कारोबार में काफी गिरावट दर्ज की गयी है। इस तरह अंकारा के पाकिस्तान-समर्थक रुख की भारत में केवल राजनीतिक आलोचना नहीं हुई, बल्कि उसका असर व्यापार, पर्यटन और तुर्किये के उत्पादों की भारतीय मांग पर भी पड़ा।

उधर, भारत की ओर से तुर्किये की नापाक नीतियों का जवाब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखता। नई दिल्ली ने तुर्किये के क्षेत्रीय रुख को देखते हुए यूनान और साइप्रस के साथ अपने रणनीतिक तथा समुद्री सहयोग को भी महत्व दिया है। संदेश साफ है। अगर अंकारा पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोलता है, तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय साझेदारियों के आधार पर जवाब देगा।

बहरहाल, एर्दोगन को कश्मीर पर उपदेश देने से पहले अपने आसपास के विवादों की ओर देखना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश को संवाद, संप्रभुता और शांतिपूर्ण समाधान की सीख देने का नैतिक आधार तभी मजबूत होता है, जब वही कसौटी अपने व्यवहार पर भी लागू की जाए। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा और तुर्किये की ऐसी हिमाकत का जवाब कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा और रणनीतिक स्तर पर भी।

'जेन-जी' आंदोलन के आईने में पंजाब और दिल्ली विवि के छात्र संघ चुनाव परिणाम

राजकुमार सिंह

जंतर-मंतर पर 'जेन-जी' आंदोलन और उसके दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार से पहली बार किसी मंत्री के इस्तीफे से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्र संघ चुनाव परिणाम चौंकानेवाले हैं। ऑनलाइन बनी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर आंदोलन शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था के विरुद्ध छात्र-युवा आक्रोश का प्रतीक बन गया था। देर से ही सही, मोदी सरकार ने उसके दबाव में झुकना बेहतर समझा। न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बल्कि आत्महत्या करनेवाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने तथा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांगें मानने की घोषणा भी दो मंत्रियों ने सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में की। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिये 'जेन-जी' से उन्हीं की भाषा में संवाद की कोशिश की, लेकिन संदेश सरकार और भाजपा का आत्मविश्वास हिल जाने का ही गया। इस परिदृश्य से विपक्षी दलों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाना स्वाभाविक ही था। जो काम विपक्ष 12 साल में नहीं कर पाया, वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी के प्रतिक्रियास्वरूप बनी सीजेपी ने चंद महीनों में कर दिखाया। जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान कुछ विपक्षी दलों की सीजेपी से नजदीकियां साफ दिखीं। जंतर-मंतर के बाद सीजेपी देश भर में स्कूलों के निरीक्षण की मुहिम चला रही है तो राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं। जंतर-मंतर के बाद हुए तीन विधानसभा उपचुनावों में से दो में भाजपा की हार को भी अन्य कारकों के साथ ही 'जेन-जी' असंतोष से भी जोड़ कर देखा-दिखाया गया। ऐसे में अगले साल सात राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और उसके विरोधी दलों के मनोबल का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, पर पीयू और डीयू के छात्र संघ चुनाव परिणामों ने राजनीतिक पंडितों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तकनीकी तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है, पर भाजपा से उसके रिश्ते छिपे नहीं हैं। इसीलिए पहले पीयू और फिर डीयू में भी एबीवीपी की जीत पर बधाई देने, जेन-जी में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बताने और विपक्ष को नसीहत देने की भाजपा नेताओं में होड़-सी लग गई। पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के छात्र ज्यादा पढ़ते हैं। स्वाभाविक ही सबसे ज्यादा दबदबा पंजाब के छात्रों का रहता है। इसीलिए पंजाब में सत्तारूढ़ आप ने युवा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को पीयू चुनाव का प्रभारी बनाया, लेकिन वह एबीवीपी को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद जीतने से नहीं रोक पाए।पीयू के बाद हुए डीयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम तो और भी चौंकानेवाले हैं। बेशक एनएसयूआई उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन एबीवीपी अध्यक्ष समेत तीन पद जीतने में सफल हो गई। एक दशक में पहली बार एनएसयूआई का खाता तक नहीं खुला। जंतर-मंतर के बाद शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था की खामियों के चलते जिस भाजपा को 'जेन-जी' के निशाने पर माना जा रहा था, उसी के द्वारा समर्थित एबीवीपी की दिल्ली विवि में ऐसी जीत साधारण घटना तो हरगिज नहीं है। डीयू से संबद्ध कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव में भी एबीवीपी का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा।

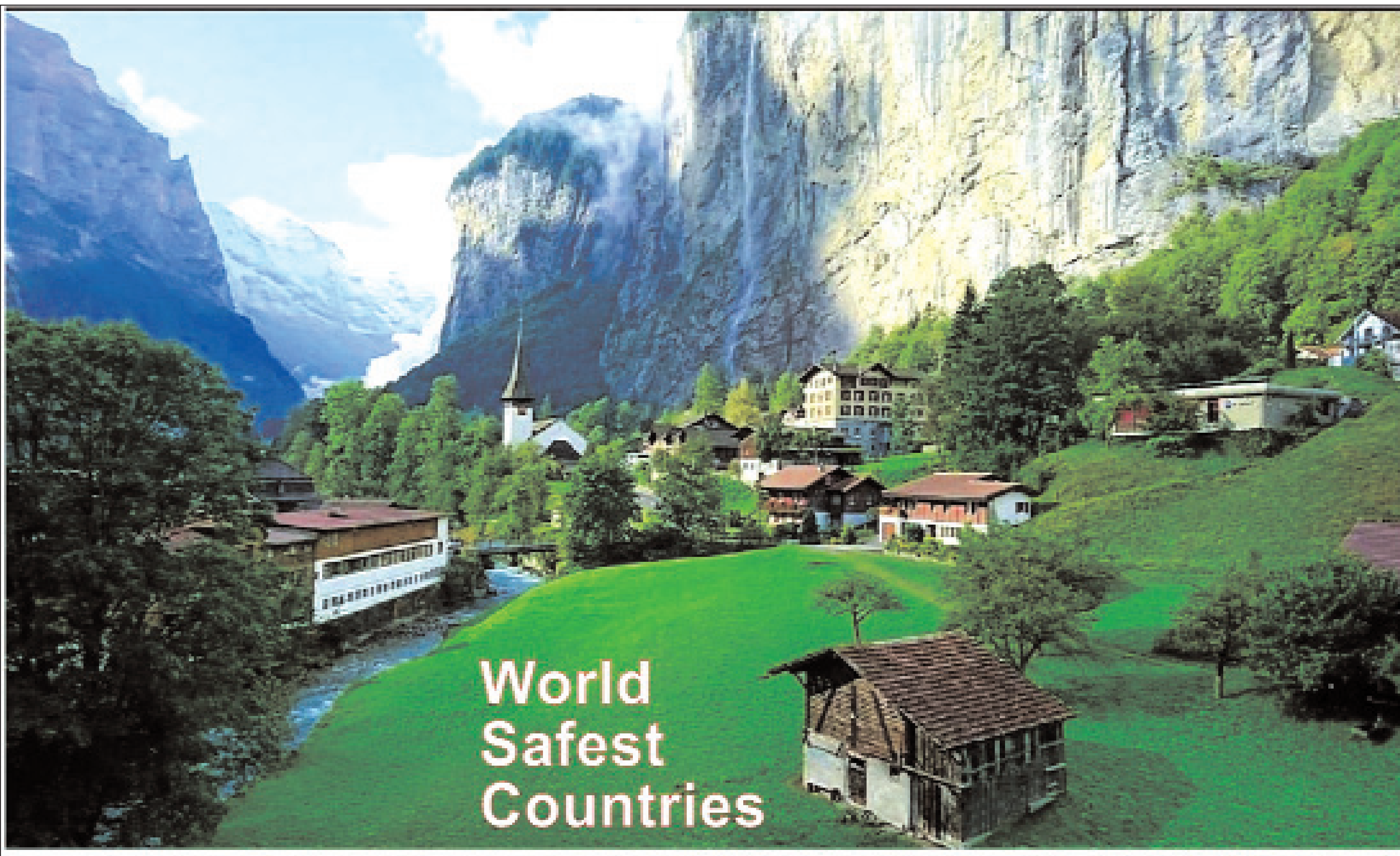

इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता, बेफिक्र होकर बनाएं घूमने का प्लान

कई लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। विदेश घूमने के लिहाज से अधिकतर देश शानदार है। हालांकि विदेशों की खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट के मन को आसानी से भा सकती है। लेकिन जब भी विदेश घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या वह जगह सुरक्षा के लिहाज से सही है। क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से देश हैं, जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड की आबादी 3,72,295 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। बता दें कि यहां पर क्राइम रेट काफी कम है। इसके साथ ही यह हाई-सिक्योरिटी वाला देश भी है। सभी तरह के अपराधों के प्रति यहां के नागरिकों का एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण है। यह देश धार्मिक स्वतंत्रता देने के साथ ही महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड सुरक्षित देश है।

न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5,124,100 के आसपास है। यह देश भी घूमने और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। यहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी क्राइम रेट कम है। हालांकि साल 2019 में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण यहां का क्राइम स्कोर थोड़ा कम हो गया है। यह पर आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शांति वाले इलाके में पुलिस अपने पास हथियार भी नहीं रखती है।

पुर्तगाल

साल 2014 के अनुसार, पुर्तगाल दुनिया का 18वां सबसे सुरक्षित देश है। ऐसे में आप बिना सुरक्षा की चिंता किए बगैर यहां पर घूम सकते हैं। 10,270,865 के करीब आबादी वाला यह देश विभिन्न कारणों से सबसे सुरक्षित देशों में शीर्ष 5वां स्थान अंकित किया है। बता दें कि आर्थिक विकास के कारण इस देश की बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आस्ट्रिया

26,177,413 के करीब जनसंख्या वाला देश आस्ट्रिया भी सुरक्षित देशों की गिनती में आता है। यहां पर भी अपराध दर काफी कम है। लेकिन यहां पर घूमने आने वाले टूरिस्टों और यहां पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को जेबकतरों और पर्स-स्नैचर्स आदि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी यहां पर घूमने आना चाहते हैं तो आपको जेबकतरों से सावधान रहने की जरूरत होगी।

डेनमार्क

डेनमार्क 5,896,026 आबादी वाला देश है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और कम भ्रष्टाचार होने के साथ ही कुशल सुरक्षाबल मिलेगा। इसके अलावा यहां की हेल्थ सुविधाएं भी काफी बेहतर हैं। इस देश में लोग आरामदायक तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।

कनाडा

कनाडा की कुल आबादी 37,742,154 के करीब है। आबादी के लिहाज से कनाडा काफी छोटा देश है। यहां का अधिकतर हिस्सा बंजर जंगल है और यह बंजर जंगल हजारों मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन घूमने के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। इस देश का अपराध दर भी काफी कम है।

सिंगापुर

सिंगापुर 59,43,546 के करीब आबादी वाला है। सिंगापुर में छोटी-मोटी चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ कुछ सख्त कानून हैं। जिसके कारण इसकी गिनती दुनिया के सुरक्षित देशों में होती है। हालांकि सिंगापुर को शहर-राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है।

जापान

जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन के आसपास है। सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे सुरक्षित देश है। चीन और उत्तर कोरिया के करीब होने के बाद भी जापान एशियाई महाद्वीप का एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में जापान हमेशा हाई स्कोर हासिल करता है।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की आबादी 10,512,397 के करीब है। यहां पर हर वर्ष अपराध दर घटता प्रतीत होता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में चेक गणराज्य सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आप सुरक्षा की परवाह किए बिना आराम से घूम-फिर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की आबादी 8.6 मिलियन के आसपास है। रहने और घूमने के लिहाज से यह देश सबसे ज्यादा बेस्ट है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी स्विट्जरलैंड दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

इन टिप्स को फॉलो कर हॉलिडे को बनाएं शानदार, ऐसे करें पैसों की बचत

कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। कई बार लगातार ट्रैवल करने के बाद भी थकान नहीं होती है। लेकिन घूमने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सेविंग्स का होना जरूरी होता है। घूमने के दौरान कई बार ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से घूमने की प्लानिंग करें तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ट्रैवल के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप ट्रैवल भी कर लेंगे और पैसों की सेविंग भी कर लेंगे।

हॉलिडे की योजना

अगर आप भी छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यह डिसाइड करें की आप रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए समुद्र तट पर चाहते हैं या एडवेंचर करना चाहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आप घूमने के लिए कहां जाने वाले हैं तो वहां होने वाले खर्चे और यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना लें। इस दौरान आपके लिए रियलिस्टिक बजट बनाना आसान हो जाएगा।

रियलिस्टिक बजट

घूमने जाने की शुरुआत हॉलिडे रियलिस्टिक बजट तय करने से शुरू होती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हों। कोई भी स्मार्ट ट्रैवलर यह बात काफी अच्छे से जानता है कि शानदार छुट्टियां बिताने के लिए एक रियलिस्टिक बजट की जरूरत होती है। जिसे आप आसानी से पहले ही बना सकते हैं।

ट्रैवल और खरीदारी

घूमने जाने के दौरान बुकिंग या खरीदारी पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। कई बार खरीददारी करने पर या बुकिंग करने के दौरान आपको कैशबैक मिलता है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ओपेन रखना चाहिए।

ऑफ सीजन में यात्रा

इस सीक्रेट को सभी स्मार्ट ट्रैवलर्स अपनाते हैं। अधिकतर ट्रैवल करने वाले ऑफ सीजन में यात्रा कर बड़ी बचत करते हैं। इस दौरान उनका ज्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि वह ऑफ-पीक हॉलिडे सीजन में ट्रैवल करते हैं। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से फ्लाइट्स, होटल आदि सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं।

फ्लाइट्स चुनते समय फ्लेक्सिबल

पर्यटकों की आवाजाही सप्ताह के कुछ दिनों में कम होती है। इस समय यात्रा करने पर आपको सस्ती उड़ान भरने का मौका मिल सकता है। फ्लाइट की कीमत के आधार पर आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे।

हॉस्पिटैलिटी कंपनी

आपको बता दें कि अपने नियमित ग्राहकों के लिए कई प्रमुख होटल चेंस और एयरलाइंस बहुत कम या बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स पेश करती हैं। इस दौरान आपको होटल चेंस और एयरलाइंस के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। यह पॉइंट अर्जित करने का एक क्विक और आसान तरीका है। जिसके बदले कई प्रमुख बैंक गिफ्टस और सर्विस के बदले में आपको रिवार्ड पॉइंट प्रदान करते हैं। जिन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है।

सस्ता विकल्प खोजें

अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उन विकल्पों का पता करें। जिनमें यात्रा सस्ती होने के साथ ही आने-जाने से लेकर रहने तक हर चीज के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। इस दौरान हॉलिडे प्लान करने के दौरान शानदार अनुभवों के लिए फ्लाइट्स के स्थान पर ट्रेनों की खोज करें।

सिक्किम घूमने का बना रहे हैं प्लान तो...

इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर, जन्नत में आने का होगा एहसास

देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का नाम गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप प्लान करने वाले अधिकतर लोग सिक्किम घूमना नहीं भूलते हैं। वैसे तो सिक्किम में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। ऐसे में अगर आप भी सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के बाद आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम भले ही एक छोटा सा राज्य है। लेकिन यहां की खूबसूरत वादियों से लेकर नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सिक्किम की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में...

त्सोमगो झील की सैर

अगर आप सिक्किम में किसी रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो त्सोमगो लेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। त्सोमगो लेक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से महज 40 किलोमीटर दूर है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस लेक को चांगु झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। वहीं बसंत ऋतु के मौके पर इस लेक की सुंदरता कई खूबसूरत फूलों से खिल उठती है।

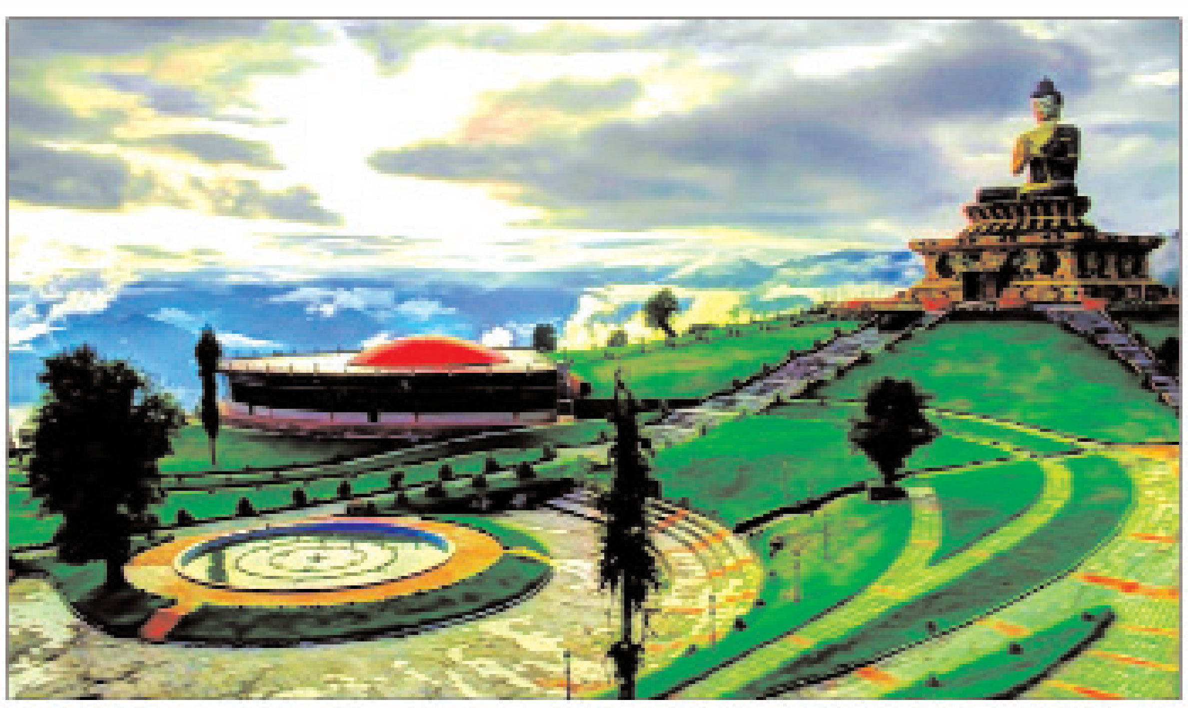

जुलुक का दीदार

जुलुक का दीदार करने के लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 3 घंटे का सफर तय करना होता है। इस दौरान रास्ते में 32 हेयरपिन मोड़ आपकी यात्रा को अधिक शानदार बना सकते हैं। वैसे तो जुलुक सिक्किम का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत गांव है। लेकिन यहां से 11 फीट की ऊंचाई पर स्थित थंबी व्यू प्वाइंट कंचनजंघा चोटी अपने खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। जुलुक की ट्रिप के दौरान कुपुप लेक या हाथी झील का भी दीदार कर सकते हैं।

पेलिंग की ट्रिप

गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यह जगह रोमांच के लिए फेमस है। पेलिंग का सफर एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। यहां पर एडवेंचर के शौकीन लोग रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सांगाचोलिंग मठ रिम्बी वॉटरफॉल रबाई रॉक और रोबांग रॉक गार्डन का दीदार कर अपने सफर को शानदार और रोमांचक बना सकते हैं।

रावंगला

रावंगला सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वतों से घिरा रावंगला मैनम और टेंडोंग हिल्स टॉप पर मौजूद है। बता दें कि रावंगला गंगटोक से लगभग 63 किलोमीटर की दूर स्थित है। नेचर लवर्स के लिए रावंगला की सैर बेस्ट हो सकती है। यहां से आप ग्रेटर हिमालय के मनमोहक नजारों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा पत्र

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मानव तस्करी से निपटने को प्राथमिकता दें। इसके लिए उन्हें तीन नए आपराधिक कानूनों वाले नवीन न्याय संहिता को पूरी तरह लागू करना होगा और कानून लागू करने की कोशिशों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार की इस अहम प्राथमिकता से निपटने में राज्य के नेतृत्व और ज़िम्मेदारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमएचए के महिला सुरक्षा विभाग ने 28 अगस्त को राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को एक विस्तृत पत्र भेजा। इसमें अधिकारियों से कहा गया कि वे भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को पूरी प्रशासनिक तत्परता के साथ अधिकतम क्षमता तक लागू करें। पत्र में कहा गया है कि इन कानूनों को लागू करने का चरण पूरा हो चुका है, और अब नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत इन्हें लागू करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य ज़िम्मेदारी है।

बीकानेर में सेवा संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 सितंबर को बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित 'सेवा संकल्प' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक पूरे देश में 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज आपने हमारे युवाओं की उस यात्रा को देखा, जो माननीय प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वड़नगर, गुजरात से शुरू होकर उनकी कर्मभूमि वाराणसी तक गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सेवा का संकल्प लेना है। शर्मा ने बताया कि उन्होंने बीकानेर का दौरा किया क्योंकि वड़नगर से वाराणसी की यात्रा के दौरान यह एक तय पड़ाव था। उन्होंने युवाओं को एक साथ मोटरसाइकिल पर यात्रा करते हुए देखकर खुशी और गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें शुभकामनाएं दीं। सेवा के काम लगातार किए जा रहे हैं।

रायबरेली पहुंची अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा

रायबरेली। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुँचने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 'पीडीए रथ' के काफिले को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लाल समाजवादी टोपी पहने समर्थकों ने जोश के साथ पार्टी के झंडे लहराए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। यादव अपनी प्रचार बस के खुले हिस्से में खड़े होकर भीड़ का अभिवादन कर रहे थे और हाईवे पर कई सौ मीटर तक जमा हुए समर्थकों के उत्साहपूर्ण नारों का जवाब दे रहे थे। रायबरेली में लोगों की यह भारी भीड़ - जो गांधी परिवार का गढ़ है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय सीट है - समाजवादी पार्टी के लिए ताकत के एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। बछरावां इलाके के चुरुआ गांव में यादव के 'पीडीए रथ' पर सवार होने के साथ ही उनके स्वागत का कार्यक्रम हुआ।

बिहार में अपराध चरम पर और पुलिस अवैध वसूली में व्यस्त

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पुलिस थानों में फैले भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि राज्य में बेकाबू अराजकता का माहौल है, जहाँ हर दिन हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में रोज़ाना हत्याएं हो रही हैं। लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है; अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का ज़िक्र करते हुए यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि पुलिस थानों और प्रशासनिक ब्लॉकों में गहरे तक फैले भ्रष्टाचार के कारण जनता की परेशानी बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस थानों और ब्लॉकों में फैले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है।

प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड हिरासत में

मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्र साहिल वाकोडे के परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए संस्थान के परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बृहस्पतिवार को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आईआईटी मुंबई में बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र वाकोडे (22) को 18 सितंबर की शाम छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। यह घटना उस समय हुई जब कुछ घंटे पहले उसे 'मिड-सेमेस्टर' परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन से चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। उसके माता-पिता ने दावा किया है कि उसने उन्हें अपने साथ जाति आधारित अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने के बारे में बताया था। गायकवाड़, कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं और पार्टी के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को संस्थान के पवई परिसर के बाहर प्रदर्शन किया।

सेवा संकल्प यात्रा: प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत

कहा- सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत की। सेवा यात्री 10 समूहों में वड़नगर से वाराणसी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत में झाबुआ जिले के एक गांव में 'मोदी फालिया' नाम रखे जाने और युवाओं के समर्थन का भी जिक्र हुआ।

प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक पुरानी कहावत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक पुरानी कहावत है कि जब कोई यात्रा से लौटता है और आप उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उस यात्रा से मिले आध्यात्मिक पुण्य का आधा हिस्सा प्रणाम करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए आज, इन सभी सेवा यात्रियों को नमन करके, मैं भी उस पुण्य का आधा हिस्सा ले रहा हूं।

पीएम मोदी ने हिस्सा लेने वालों से अपना ध्यान रखने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि सेवा ही मुख्य मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा, सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। हमें सिर्फ उपदेश देकर नहीं, बल्कि खुद सेवा करके सेवा का संदेश देना चाहिए। हम अपने कामों से सेवा का संदेश देंगे, सिर्फ बातों से नहीं।

उन्होंने कहा कि हिस्सा लेने वालों का व्यवहार लोगों को यह दिखाना चाहिए कि चाहे कितनी भी राजनीतिक ताकत क्यों न मिल जाए, रास्ता सेवा का ही होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हमारा व्यवहार लोगों को यह दिखाना चाहिए कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों न मिले, हमारा रास्ता सेवा का ही रहता है।

पीएम मोदी ने कहा, हम सेवा के इस रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। हम चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर लें, हम हमेशा सेवा परमो धर्म (सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है) के सिद्धांत का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल 35,500 किलोमीटर की दूरी 20 टीमें तय करेंगी, जिनका एक ही संकल्प होगा - सेवा।

यह पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को उजागर करने वाले बड़े सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल लोग कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों की यात्रा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सेवा और लोगों की भागीदारी वाली गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।

बता दें कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक, ये टीमें वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर तक का सफर करेंगी। उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की है जो सिर्फ एक मोटरसाइकिल यात्रा से कहीं ज्यादा है। वे कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से गुजरते हुए सेवा की भावना को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। यह पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को उजागर करने वाले बड़े सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर चले देशद्रोह का केस: प्रियंका गांधी

नईदिल्ली। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार पर अनुचित चुनाव कराने के लिए देशद्रोह का आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करता है, वह देश के खिलाफ देशद्रोह करता है; साथ ही, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना और 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक कृत्य है।

उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमारे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पद पर बैठे किसी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना और 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना लोकतंत्र, संविधान और देश के ख़िलाफ़ एक आपराधिक काम है... अगर चुनाव आयुक्त ने कोई ग़ैर-कानूनी काम किया है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह पता था कि यह सब उनकी नाक के नीचे हो रहा है; उनके साथियों ने इस ओर उनका ध्यान भी दिलाया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज़ किया और जान-बूझकर एक निष्पक्ष न होने वाले चुनाव को होने दिया। उन पर भी किसी दूसरे अपराधी की तरह ही आपराधिक मुक़दमा चलना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने की कोई भी कोशिश संविधान और देश के ख़िलाफ़ एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब बिल्कुल साफ़ है। जो कोई भी हमारे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर गैर-कानूनी काम साबित हो जाते हैं, तो सीईसी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को—यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को—तब भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जब उन्होंने गैर-कानूनी काम किए हों।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना और बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना, 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना... लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक काम है। प्रियंका गांधी ने आगे आरोप लगाया कि अगर सीईसी को गड़बड़ियों के बारे में पता था, या साथी आयुक्तों ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी और फिर भी उन्होंने इसे जारी रहने दिया, तो उन पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का यह बयान इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान वोटर लिस्ट की प्रक्रियाओं और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

सीईसी ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें : कांग्रेस

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि इस "घिनौनी साजिश" के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गोवा में 97 मतदाताओं के मामलों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने दस्तावेजों की जांच करने और सुनवाई के बाद उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने योग्य पाया था, लेकिन "ईसीआईनेट" सॉफ्टवेयर में उन्हें दोबारा शामिल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं था।

भाजपा ने बदला संगठन का ढांचा

कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त

नई दिल्ली। भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 24 सितंबर 2026 को संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की। इनमें राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी स्तर के पद शामिल हैं। नियुक्तियों के जरिए कई राज्यों में संगठन की जिम्मेदारियां अलग-अलग नेताओं को सौंपी गई हैं। इससे पहले कल भाजपा ने सभी प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारी की सूची जारी की थी। इस सूची में स्मृति ईरानी, सुनील बंसल और अमिल मालवीय का भी नाम था।

नई नियुक्तियों के जरिए अलग-अलग राज्यों के संगठन में जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं।

शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) बनाया गया है। उन्हें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उनका केंद्र मुंबई होगा। सौदान सिंह को भी राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) की जिम्मेदारी मिली है। उनके जिम्मे बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल होंगे और केंद्र भुवनेश्वर रहेगा। वी. सतीश को एससी, एसटी मोर्चा और संसदीय कार्यालय से जुड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। नगेंद्र को वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क की जिम्मेदारी मिली है। दोनों का केंद्र दिल्ली रहेगा।

महाराष्ट्र में अजय जामवाल को राज्य महासचिव (संगठन) बनाया गया है, जबकि सतीश धोंड को महाराष्ट्र के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े जनजाति संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। मधुकर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राज्य महासचिव (संगठन) बनाया गया है। दशरथ तेलंगाना के राज्य संयुक्त महासचिव (संगठन) होंगे। रविंद्र राजू को असम, त्रिपुरा और कार्यालय निर्माण की जिम्मेदारी मिली है।

भिखूभाई दलसानिया को बिहार, पवन साई को झारखंड, सिद्धार्थन को हिमाचल प्रदेश, रत्नाकर को गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की जिम्मेदारी मिली है। अरुण बिन्नाडी गुजरात के राज्य संयुक्त महासचिव (संगठन) होंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

सेमीफाइनल में पहुंचीं भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमें

नागोया। भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने एशियाई खेल 2026 में अपने-अपने ग्रुप चरण का अभियान अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को पुरुष टीम ने चीनी ताइपे के खिलाफ ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ टाइम तक 23-11 की बढ़त बना ली। दोनों टीमें अब अपने खिताब का बचाव करने से महज दो जीत दूर हैं।

डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया। भारत ने हाफ टाइम तक 23-11 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप चरण में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश को हराया था। चीनी ताइपे के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबले में भी भारत ने अपना दबदबा कायम रखा और बिना कोई मैच गंवाए अंतिम चार में प्रवेश किया।

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी ग्रुप चरण में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। टीम ने अपने पहले मुकाबलों में बांग्लादेश और ईरान के खिलाफ जीत दर्ज की थी। गुरुवार को आखिरी ग्रुप मुकाबला पूरा करने के साथ ही भारतीय टीम ने अंतिम चार में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। भारत की पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमें अब एशियाई खेलों में अपने-अपने खिताब का बचाव करने से सिर्फ दो जीत दूर हैं। दोनों टीमों के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। ऐसे में भारत के पास कबड्डी में डबल गोल्ड हासिल करने का मौका बना हुआ है। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को दो अलग-अलग सत्रों में खेले जाएंगे। मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10:45 बजे और दोपहर 3:45 बजे के सत्र में होंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1,247 अंक लुढ़क कर 73,580 पर बंद

मुंबई। गुरुवार को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1,247.71 अंक या 1.67 फीसदी की गिरावट के साथ 73,580.54 पर आ गया। वहीं निफ्टी 383.70 अंक यानी 1.64 फीसदी गिरकर 23,063.10 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा को छोड़कर ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। अमेरिका में 10-साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 2007 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना के कारण ऐसा हुआ है। यह यील्ड 13.89 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.106त्न हो गई, जो 2007 के बाद सबसे ज्यादा है और अप्रैल 2025 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त थी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से डेट मार्केट ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इससे अक्सर इक्विटी मार्केट में कुछ गिरावट आती है।

कच्चा तेल महंगा, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले दिनों 100 से 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि, इस बढ़ोतरी का तत्काल असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ने की संभावना नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार की नजर लगातार अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक स्तर पर बदल रही परिस्थितियों पर बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद पेट्रोल-डीजल की मौजूदा कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है।

1 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया नियम

नई दिल्ली। फिक्स्ड डिपॉजिट(एफडी) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से बैंक एफडी से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य एफडी की ब्याज दरों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को सही जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। नए नियमों के तहत किसी बैंक की अलग-अलग शाखाओं में समान अवधि वाली एफडी के लिए लागू ब्याज दर एक जैसी होनी चाहिए यानी किसी शहर या स्थान के आधार पर एक ही बैंक की समान अवधि वाली एफडी की ब्याज दर अलग-अलग नहीं होगी। इसके साथ ही बैंकों को एफडी पर लागू ब्याज दरों की जानकारी ग्राहकों को पहले से उपलब्ध करानी होगी। बैंक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित एफडी योजनाओं को सार्वजनिक करना होगा।

त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेंगे खाद्य तेलों के दाम

नईदिल्ली। आगामी त्योहारी सीजन से पहले खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोत्तरी रोकने के लिए सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाने के तेल पर आयात शुल्क कम कर दी है। पिछले एक साल में घरेलू वेजिटेबल ऑयल की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह कदम सितंबर से नवंबर तक चलने वाले बड़े त्योहारी सीजन से पहले उठाया गया है, जब मिठाइयों, स्नैक्स और तली-भुनी चीज़ों की मांग से आमतौर पर खाने के तेल की खपत बढ़ती है। आयात लागत कम होने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों के लिए इसे खरीदना आसान हो सकता है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल और कच्चे सोया ऑयल पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।

भारत के विनिर्माण सपने के लिए कौशल विकास में बड़े बदलाव की जरूरत

देवाशिष बसु

भारत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को विकास, निर्यात और रोजगार का एक बड़ा इंजन बनाना चाहता है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, मशीनरी, वस्त्र, औष ?धि और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, औद्योगिक गलियारे, रसद (लॉजिस्टिक्स) में निवेश और वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करने के प्रयास, ये सभी इसी दिशा में इशारा करते हैं। लेकिन कारखानों को केवल जमीन, बिजली और पूंजी से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है।

उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मशीनें चला सकें, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ सकें, औद्योगिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकें, विद्युत प्रणालियों को स्थापित और उनका रखरखाव कर सकें, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को संचालित कर सकें और तेजी से स्वचालन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल सकें। लेकिन भारत में श्रम शक्ति तो बहुत अधिक है, पर औपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या कम है।

कई कंपनियां, विशेषकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में, अपने स्वयं के कौशल विकास कार्यक्रम चलाती हैं। लेकिन ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के लिए बहुत छोटे हैं। वर्ष 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 से 29 आयु वर्ग के केवल 4.9 फीसदी भारतीयों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अन्य 21.2 फीसदी ने अनौपचारिक स्रोतों से कौशल हासिल किया था। औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल एक छोटे से वर्ग तक ही पहुंच पाता है। बेशक, भारत का दावा है कि उसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया है।

इस वर्ष जून तक सरकार के प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 1.65 करोड़, जन शिक्षण संस्थान के तहत 36.6 लाख, राष्ट्रीय ?प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 53 लाख और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 1.07 करोड़ लोगों की संचयी भागीदारी दर्ज की गई है।

इन आंकड़ों को जोड़ने पर कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या 3.2 करोड़ से अधिक हो जाती है। लेकिन ये लोग विशिष्ट रूप से कुशल श्रमिक नहीं हैं। ये योजनाएं विभिन्न गतिविधियों, अवधियों और श्रेणियों को कवर करती हैं, और अप्रेंटिस ?शिप (प्र ?शिक्षुता) किसी स्थायी कौशल योग्यता के बराबर नहीं होती। अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रशिक्षण के बाद क्या होता है? क्या श्रमिक उत्पादक कार्य कर सकता है? क्या नियोक्ता उसकी योग्यता को मान्यता देता है?

क्या कौशल किसी विशेष कारखाने की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा? आइए देश के सबसे बड़े विनिर्माण उद्योगों में से एक, वाहन उद्योग पर विचार करें। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा उद्योग परामर्शों पर आधारित एक हालिया अध्ययन में पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ नए व्यवसायों में भी कमी पाई गई।

क्या किया जाना चाहिए? हमेशा की तरह, चीन और अन्य एशियाई देशों से सीखना अच्छा है जिन्होंने तीव्र औद्योगीकरण के लिए आदर्श स्थापित किए हैं। तीव्र कौशल विकास के बिना यह असंभव है। वर्ष 1978 में चीन द्वारा अर्थव्यवस्था खोलने और सुधारों को अपनाने के बाद, कौशल संबंधी समस्या के प्रति देश की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सीधी थी। उसने औद्योगीकरण वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की संरचना में परिवर्तन किया।

वर्ष1978 में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों का मात्र 7.6 फीसदी थी। वर्ष 1985 के शिक्षा सुधार ने व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को एक केंद्रीय उद्देश्य बनाया, जिसका लक्ष्य बुनियादी से लेकर उन्नत स्तर तक तकनीकी शिक्षा की एक प्रणाली का निर्माण करना और इसे विभिन्न उद्योगों से जोड़ना था।

राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित छग के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत : विष्णु देव

छह लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा एआई प्रशिक्षण

मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान

रायपुर। युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार की क्षमता और सेवा भावना को सही दिशा देकर समाज और राष्ट्र में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर सभी स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दीं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना

आज देश के लाखों युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला व्यापक अभियान बन चुकी है। एनएसएस से जुड़ने वाला युवा केवल गतिविधियों में भाग नहीं लेता, बल्कि समाज और अपने आसपास की परिस्थितियों को अधिक संवेदनशीलता से समझना सीखता है। लोगों की समस्याओं को समझना, जिम्मेदारी लेना, टीम के साथ कार्य करना और समाधान के लिए स्वयं आगे आना – ये ऐसे संस्कार हैं, जो युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि सेवा के किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार एक युवा द्वारा किया गया छोटा-सा प्रयास भी पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। किसी गांव में स्वच्छता के लिए पहल करना, जरूरतमंद के लिए रक्तदान करना, पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना अथवा किसी व्यक्ति को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना – ऐसे प्रयास समाज में बड़े परिवर्तन की नींव बनते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से 'मेरा युवा भारत' जैसा व्यापक मंच तैयार किया गया है।

विकसित भारत की यात्रा में युवा निभाएंगे निर्णायक भूमिका

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत का यह लक्ष्य केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवाओं का साझा संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, परिश्रम, नवाचार और सेवा भावना इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। आज एनएसएस के माध्यम से सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का जो संस्कार युवा अपने भीतर विकसित कर रहे हैं, वही आने वाले समय में उन्हें राष्ट्र निर्माण का सक्षम नेतृत्व प्रदान करेगा।

उप मुख्यमंत्री साव व शर्मा ने रखी कवर्धा के नए स्वरूप की नींव

54 करोड़ से बनेगी 4 लेन सड़क

कवर्धा। शहर में प्रवेश करते ही अब बदलता हुआ शहर नजर आएगा। 54 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर 7.8 किलोमीटर सड़क को 4 लेन में विकसित करने के साथ रायपुर और बिलासपुर की ओर दोनों प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज शहर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नया मंडी परिसर, कवर्धा में इस सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया। चंद्रयान हॉस्पिटल से शुरू होकर कवर्धा शहर के प्रमुख हिस्सों से गुजरते हुए जोराताल के आगे तक बनने वाली इस 4 लेन सड़क में डिवाइडर का भी निर्माण किया जाएगा।

प्रवेश द्वारों के डिजाइन में धर्मनगरी कवर्धा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कवर्धा नगर पालिका में सामुदायिक भवन निर्माण और मटन मार्केट के लिए 3.50 करोड़ रुपए, नगर पंचायत बोड़ला में बाजार विस्थापन के लिए 1.50 करोड़ रुपए, सहसपुर लोहारा में बाधांटोला में गौरव पथ निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपए और नगर पंचायत पिपरिया के खेल मैदान के लिए 1.50 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की।

विकसित भारत की थीम पर दिव्यांग विद्यार्थियों ने उकेरे सपनों के रंग

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय, तिफरा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं द्वारा 'विकसित भारत' की थीम पर पेंटिंग एवं रंगोली तैयार की गई। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करते हुए रंगों के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग एवं रंगोली में स्वच्छ एवं सुंदर भारत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भरता, तकनीकी विकास,

पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा देश की प्रगति जैसे विषयों को प्रमुखता से दर्शाया। रंग-बिरंगे चित्रों और आकर्षक रंगोली के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश के उज्ज्वल भविष्य और विकास की अपनी कल्पना को अभिव्यक्त किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हुए उनमें देश के विकास के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से यह संदेश दिया कि अवसर और प्रोत्साहन मिलने पर वे भी समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत आज होगा श्रमदान तालाब सफाई अभियान

रायपुर। स्वच्छता ही सेवा 2026 एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत श्रमदान – तालाब सफाई अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें महाराजबंध तालाब, मठपारा, रायपुर में 25 सितंबर 2026 को समय – सुबह 7.00 बजे से किया जाएगा।

रायपुर शहर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महाराज बंध तालाब को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग की अपील की है।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की फॉलो-अप बैठक

अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के विभिन्न विभागों की समय-सीमा फॉलो-अप बैठक ली।

बैठक में कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाता सुधार की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जोन में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर करने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाते हुए मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में एग्रीस्टैक की प्रगति की भी जानकारी ली गई।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित जिले के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

विद्यार्थियों ने रक्तदान कर पेश की सेवा की मिसाल

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए अपना योगदान दिया।

शिविर में कुल 23 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान को लेकर विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों में उत्साह नजर आया। उन्होंने रक्तदान को मानव सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए बढ़-चढ़कर सहभागिता की। शिविर का उद्देश्य युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के साथ उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना को बढ़ावा देना रहा। विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों की सहभागिता ने सेवा कार्यों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से आयोजित इस शिविर में रक्तदान के महत्व का संदेश भी दिया गया।

बारिश का सिलसिला जारी हैदराबाद फ्लाइट हुई रद्द

जगदलपुर। बस्तर में बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब के चलते पिछले दो दिनों से आसमान में घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश जारी रही, वहीं गुरूवार सुबह से

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के भारी बारिश के अनुमान के अनुसार मूसलाधर बारिश का सिलसिला जारी है। जिसके चलते बस्तर जिले में 24 सितंबर को सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित दिया गया, वहीं गुरुवार को जगदलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। मौसम खराब होने से 30 से अधिक यात्री हैदराबाद के लिए रवाना नहीं हो सके। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश और बादल बने रहे तो हवाई सेवा प्रभावित हो सकती है। सितंबर में अब तक बस्तर जिले में 156.6 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 11 मिमी. अधिक है। जगदलपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को मौसम खराब होने के कारण हैदराबाद की उड़ान का संचालन नहीं हो सका। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और मूसलाधर बारिश का दौर जारी रहा।

महिलाओं ने रक्तदान कर जीवन बचाने का दिया संदेश

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन, रक्तदान महाकुंभ एवं वृहद स्वास्थ्य जांच शिविर में

महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते हुए रक्तदान को लेकर बनी झिझक और भ्रांतियों को पीछे छोड़ने का संदेश दिया। इसी क्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कर्मचारी श्रीमती मोना चौधरी ने पहली बार रक्तदान कर समाज के सामने प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रीमती मोना चौधरी ने बताया कि यह उनका पहला रक्तदान था। शुरुआत में मन में थोड़ी झिझक और डर था, लेकिन जब उन्हें यह समझ आया कि उनके रक्त की एक यूनिट किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में उपयोगी हो सकती है, तो उन्होंने रक्तदान का निर्णय लिया। रक्तदान के बाद उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मानव सेवा के इस कार्य से उन्हें बेहद अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर यह धारणा देखने को मिलती है कि महिलाएं रक्तदान नहीं करतीं, लेकिन रक्तदान महाकुंभ में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने इस सोच को बदलने का संदेश दिया है। महिलाएं भी समाज और मानवता की सेवा में पुरुषों के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में झूम उठा पंडाल चारों ओर गूंजा बधाई हो

रायपुर। श्रीमद्भागवत कथा में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग के बीच मंडी ग्राउंड में भक्ति और आस्था का सैलाब इस तरह झूम रहा था कि चारों तरफ केवल एक ही गूंज सुनाई पड़ रहा था ..बृज की गली-गली में मचा है शोर,आयो है माखन चोर,जनम लियो हैं कृष्ण कन्हाई। जनम लियो है यशोदा के लाला। बधाई हो बधाई। पंडाल के बीचो बीच बने कारीडोर में घूम-घूम कर भक्तों के बीच इन्द्रेश जी महाराज, सेवादार गुंजन प्रजापति मिष्ठान,चाकलेट,टाफी,खिलौने,माखन मिश्री और फूलों की वर्षा कर रहे थे। भक्ति गीत के बीच सोहर भी गाये जा रहे थे और भक्त सुर ताल मिलाते हुए जमकर नाच रहे थे।

नगर पंचायत के नगरीय निकाय चुनावी गतिविधियां हुई तेज

बीजापुर। जिले के भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ नगर पंचायत क्षेत्रों में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा-कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में इस बार अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा में दावेदारों की संख्या चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर करीब 15 नामों की दावेदारी की चर्चा है, हालांकि भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता या अधिकृत पर्यवेक्षक की ओर से किसी भी नामों की पुष्टि नहीं की गई है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं। स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार पिछले चुनाव में सभी 15 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हुए थे, और नगर पंचायत अध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास रहा। ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा का विशेष ध्यान भोपालपट्टनम नगर पंचायत दिया जा रहा है। दूसरी ओर भैरमगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच स्थिति अपेक्षाकृत करीबी मुकाबला माना जा रहा है। नगर पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा संगठन की ओर से बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर जारी है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के प्रभारी मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भी चुनावी तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं।

लमना में दिखी संस्कृति और अपनत्व की खूबसूरत तस्वीर

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा ग्रामीण पर्यटन मॉडल

लमना विलेज स्टे में ब्रिटेन के अतिथियों ने ग्रामीण जीवन, स्थानीय संस्कृति और हाट-बाजार का लिया अनुभव

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, ग्रामीण जीवनशैली, लोक संस्कृति और आत्मीय आतिथ्य अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। पर्यटन के बदलते स्वरूप में अब पर्यटक केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे गांवों की मिट्टी की खुशबू, स्थानीय खान-पान, परंपराओं, हस्तशिल्प और ग्रामीण जीवन को करीब से अनुभव करने में भी रुचि ले रहे हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लमना विलेज स्टे में ब्रिटेन से पहुंचे पर्यटकों का प्रवास इसी बदलती पर्यटन तस्वीर की जीवंत मिसाल है।

ब्रिटेन से आए श्री फ्रैंक रोजर मार्सटन और श्रीमती जेनिफर मार्गरेट रेनफ्रू मार्सटन का लमना गांव पहुंचने पर ग्रामीणो ने पारंपरिक आत्मीयता के साथ तिलक लगाकर तथा ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच स्वागत किया। विदेशी अतिथियों ने भी ग्रामीणों के इस आत्मीय स्वागत का आनंद लिया और स्थानीय लोगों के साथ

सहजता से घुल-मिलकर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति को करीब से महसूस किया। लमना विलेज स्टे में अतिथियों का अनुभव केवल ठहरने तक सीमित नहीं रहा। उन्हें गांव की गलियों, खेत-खलिहानों, पारंपरिक परिवेश और स्थानीय जीवन से परिचित कराने के लिए विलेज वॉक कराया गया। इस दौरान अतिथियों ने ग्रामीणों से संवाद किया, स्थानीय जीवनशैली को समझा और गांव के सहज वातावरण का आनंद लिया। अतिथियों ने ग्रामीण परिवारों, बच्चों, महिलाओं और स्थानीय लोगों के साथ आत्मीय संवाद भी किया।

लमना प्रवास के दौरान स्थानीय ग्रामीण हाट का भ्रमण विदेशी मेहमानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

स्टेशनरी दान से बच्चों की पढ़ाई को मिलेगा संबल, 118 नागरिकों ने बढ़ाया सहयोग का हाथ

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने बच्चों के पढ़ाई के लिए स्टेशनरी सामग्री दान की

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर जिले में सेवा और सामाजिक सहभागिता से जुड़े छह विभिन्न सेवा अभियानों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आयोजित स्टेशनरी दान अभियान में नागरिकों ने जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए सेवा की मिसाल पेश की। अभियान में 118 नागरिकों ने सहभागिता करते हुए स्टेशनरी सामग्री दान की। प्रमुख

सचिव श्रीमती निहारिका बारिक एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी स्टेशनरी सामग्री दान कर अभियान में सहभागिता की। इतनी सामग्री हुई एकत्र 498 कॉपी, 502 पेन, 350 रबर वाली पेंसिल, 375 बिना रबर वाली पेंसिल, 320 वैक्स पेंसिल, 150 स्केच पेन, 215 स्केल, 23 पेन पैकेट, 11 कंपास बॉक्स, 55 पैकेट गोंद, सहित 3 स्कूल बैग, 6 टिफिन बॉक्स और 5 पानी की बोतल।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.